

किसानों ने पंजाब में 3 घंटे रेलवे ट्रैक जाम किए

● चंडीगढ़ में एसकेएम की इमरजेंसी मीटिंग, डल्लेवाल को समर्थन पर फैसला

लुधियाना/जालंधर/मोहाली (एजेंसी)। शंभू बॉर्डर और खनौरी बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन के समर्थन में आज किसानों ने पंजाब में 3 घंटे रेलवे ट्रैक जाम किए। किसान दोपहर 12 बजे 48 जगहों पर ट्रैक पर बैठ गए। 3 बजते ही किसानों ने ट्रैक खाली कर दिए। रेलवे ट्रैक जाम होने से दिल्ली-पठानकोट सुपरफास्ट एक्सप्रेस को लुधियाना के डंडारी कलां में रोकना पड़ा। कुछ ट्रेनों को कैसिल तो कुछ को डायवर्ट भी करना पड़ा। किसानों के प्रदर्शन से करीब 60 ट्रेनों की आवाजाही पर असर पड़ा।

● अनशन कर रहे डल्लेवाल पर कहा- वे जननेता, उनका स्वस्थ रहना जरूरी, तुरंत इलाज कराएं

पटियाला (एजेंसी)। किसान आंदोलन पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसानों के लिए हमारे दरवाजे हमेशा खुले हैं। वे सीधे अपने सुझाव या मांगें लेकर हमारे पास आ सकते हैं या अपना प्रतिनिधि भेज सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने खनौरी बॉर्डर पर आमरण अनशन कर रहे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल की तबीयत पर भी पंजाब सरकार से जवाब मांगा। पंजाब के अटॉर्नी जनरल गुरमिंदर सिंह ने कहा, डल्लेवाल के साथ बातचीत हुई है। उन्होंने अपने मेडिकल टेस्ट करवाने से इनकार कर दिया है। उनके सभी जरूरी अंग सही तरह से काम कर रहे हैं।

संक्षिप्त समाचार

अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से अश्विन ने अचानक लिया संन्यास

सीरीज बीच में छोड़कर लौटेंगे घर

ब्रिस्बेन (एजेंसी)। भारत के दिग्गज स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने का फैसला किया है। उन्होंने गाबा टेस्ट के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी घोषणा की। अश्विन कप्तान रोहित शर्मा के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंचे थे और वहां इसकी घोषणा की। संन्यास से पहले अश्विन ड्रेसिंग रूम में विराट कोहली के साथ बैठे नजर आए थे। इस दौरान कोहली ने उन्हें गले भी लगाया था। अश्विन एडिलेड डे नाइट टेस्ट में टीम इंडिया का हिस्सा रहे थे। भारत के लिए कई रिकॉर्ड बना चुके अश्विन- 38 साल का यह स्पिनर भारत के लिए कई रिकॉर्ड बना चुका है। वह टेस्ट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वालों में सातवें स्थान पर हैं। अश्विन के नाम 106 टेस्ट में 537 विकेट हैं। 59 टेस्ट दैकर सात विकेट उनकी सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी है।

गेटवे ऑफ इंडिया के पास फेरी बोट पलटी, 13 की मौत

मुंबई (एजेंसी)। मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया के नजदीक फेरी बोट के पलटने की घटना सामने आई है। यह बोट ट्रिस्टर को एलीफंटा ले जा रही थी। तभी इस नाव का संतुलन बिगड़ गया। वीडियो में काफी लोगों के सवार होने की पुष्टि हुई है। मुंबई पुलिस और भारतीय नौसेना बचाव अभियान चला रही है। अभी तक 13 यात्रियों की मौत की पुष्टि की गई है। नाव में कुल 56 यात्री सवार थे। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने घटना पर संज्ञान लेते हुए कहा है कि रेस्क्यू ऑपरेशन सभी एजेंसियों को काम पर लगा दिया गया है। फेरी बोट हादसे में अभी तक 21 लोगों को बचा लिया गया है। प्रशासन ने एक मौत की पुष्टि की है। अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। रेस्क्यू किए गए लोगों को उपचार के लिए भेजा गया है। काफी लोग बुरी तरह से डरे हुए हैं। शुरुआती जानकारी में सामने आया है कि नाव एलीफंटा जा रही थी।

वन नेशन-वन इलेक्शन जेपीसी के लिए प्रियंका का नाम कांग्रेस ने 3 और सांसदों को नॉमिनेट किया

नई दिल्ली (एजेंसी)। एक देश, एक चुनाव के लिए संसद में मंगलवार को पेश हुए 129वां संविधान (संशोधन) बिल की समीक्षा के लिए बनने वाली जॉइंट पार्लियामेंटरी कमेटी (जेपीसी) में कांग्रेस की तरफ से प्रियंका गांधी शामिल हो सकती हैं। कांग्रेस ने जेपीसी के लिए चार सांसदों के नाम नॉमिनेट किए हैं। इनमें प्रियंका के अलावा मनीष तिवारी, रणदीप सिंह सुरजेवाला और सुखदेव भगत सिंह शामिल हैं। वहीं, तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) ने साकेत गोखले और कल्याण बनर्जी का नाम आगे बढ़ाया है।

अंबेडकर-अडाणी-मणिपुर मुद्दे पर कांग्रेस का देशभर में प्रदर्शन

यूपी में यूथ कांग्रेस महासचिव की मौत

राजस्थान में गहलोत-पायलट एक मंच पर आए, बिहार में पुलिस ने पैदल मार्च रोका

नई दिल्ली/जयपुर/पटना (एजेंसी)। कांग्रेस पार्टी अमित शाह के अंबेडकर पर दिए बयान, अडाणी मुद्दे और मणिपुर हिंसा को लेकर आज देशभर में विरोध प्रदर्शन कर रही है। पार्टी सभी राज्यों के राजभवन तक मार्च निकाल रही है। राजस्थान के जयपुर में कांग्रेस के प्रदर्शन में पूर्व सीएम अशोक गहलोत और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट एक मंच पर नजर आए। बिहार के पटना में कांग्रेस के राजभवन मार्च को पुलिस ने रोक दिया। वहीं प्रदर्शन के दौरान यूपी में यूथ कांग्रेस महासचिव की मौत हो गई। हैदराबाद में कांग्रेस ने नेकलेस रोड स्मारक से राजभवन तक ‘चलो राज भवन’ रैली निकाली- तेलंगाना के हैदराबाद में कांग्रेस ने नेकलेस रोड स्मारक से राजभवन तक ‘चलो राज भवन’ रैली निकाली। जम्मू में जेकेपीसीसी के अध्यक्ष तारिक हमीद और हैदराबाद में रेंवत रेड्डी के नेतृत्व में मार्च निकाला गया। असम के गुवाहटी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन- असम के गुवाहटी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राजभवन के बाहर प्रदर्शन करते हुए बैरिकेड पर चढ़ने की कोशिश की। पटना में राजभवन मार्च को प्रशासन ने रोक दिया बिहार के पटना में कांग्रेस पार्टी के राजभवन मार्च को प्रशासन ने रोक दिया है। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने पुलिस से धक्का-मुक्का भी की। मार्च रोकने के बाद विरोध में पार्टी के कार्यकर्ता बीच सड़क पर धरने पर बैठ गए। सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कांग्रेसियों ने कारोबारी गौतम अडाणी की गिरफ्तारी की मांग और मणिपुर हिंसा को लेकर केंद्र सरकार की आलोचना की। राजस्थान – कांग्रेस ने पैदल मार्च कर राजभवन का घेराव किया – राजस्थान के जयपुर में कांग्रेस ने पैदल मार्च कर राजभवन का घेराव किया जाएगा। सचिन पायलट ने कहा कि कौन नेता आया, नहीं आया। इधर-उधर की बातें छोड़ो। सब एक हैं। एक साथ लड़ेंगे और चार साल बाद सरकार लेकर आएंगे। नेता प्रतिपक्ष टीकराम जूली ने कहा- अंबेडकर का नाम लेना फैशन है तो हम यह फैशन करेंगे। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डेटासरा ने कहा कि विश्व लंबे समय से अडाणी मामले में जेपीसी बनाने की मांग कर रहा है।

मेले में वनोपज एवं हर्बल उत्पाद की 10 लाख से अधिक की बिक्री

नर्सरी के औषधीय पौधे आकर्षण का केन्द्र

भोपाल। अंतर्राष्ट्रीय वन मेला-2024 में वनोपज एवं हर्बल उत्पाद की अभी तक 10 लाख से अधिक की बिक्री हुई है। आगंतुकों के लिये नर्सरी के औषधीय पौधे आकर्षण का केन्द्र रहे। वन मेले की लोकप्रियता से राजधानी ही नहीं बरन् आसपास के जिलों से लोग मेले में आ रहे हैं। मेले में स्थापित ओपीडी में बड़ी संख्या में आगंतुकों ने निःशुल्क चिकित्सकीय परामर्श किया। आयुर्वेदिक चिकित्सकों और अनुभवी वैद्यों ने निःशुल्क सेवाएं दीं। अंतर्राष्ट्रीय वन मेले में लघु वनोपज, प्रसस्करण एवं अनुसंधान केन्द्र के विन्ध्य हर्बल ब्राण्ड उत्पादों जैसे शहद, च्यवनप्राश एवं त्रिकुट को उनके प्रभावी असर एवं गुणवत्ता की वजह से काफी सराहा जा रहा है। प्रधानमंत्री वन-धन योजना के अंतर्गत मध्यप्रदेश एवं अन्य राज्यों में संचालित वन धन केन्द्रों के उत्पादों की मेले में बिक्री के प्रति लोगों का बहुत रुझान रहा। इन उत्पादों में महूए एवं देशी मोटे अनाज (मिलेट्स) के प्रति बढ़ती लोकप्रियता ने देशी महूए के लड्डू, अचार, महुआ कुकीज, कोदो-कुटको, अलसी लड्डू, तिल लड्डू, देशी मक्का कुकीज, आंवला पाचक ने लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। आगंतुकों ने बड़ी उत्सुकता के साथ इन उत्पादों को खरीदा।

नदियों के संगम से मध्यप्रदेश-राजस्थान को मिलेगा जल-शक्ति का सदा-उर्वरा आशीष : मुख्यमंत्री

संबोधित करते हुए मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को ‘लाइट’ कहा। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि पार्वती-कालीसिंध-चंबल नदी जोड़ो परियोजना से मध्यप्रदेश और राजस्थान को सिंचाई का पानी भी मिलेगा और पेयजल भी। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि पीकेसी परियोजना दोनों राज्यों की नदियों को सदानीरा बनाए रखेगी, इससे इन नदियों से संबद्ध भूमि शस्य-श्यामला बनेगी। पीकेसी परियोजना से मध्यप्रदेश को 3,000 और राजस्थान को 4,103 एमसीएम (मिलियन क्यूबिक मीटर) पानी मिलेगा। प्रधानमंत्री श्री मोदी, मुख्यमंत्री डॉ. यादव, राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा और केन्द्रीय जल शक्ति मंत्री श्री सी. आर. पाटिल की मौजूदगी में केन्द्र सरकार और दोनों राज्य सरकारों के अधिकारियों द्वारा परियोजना के लिए 17 दिसंबर 2024 को एमओए के साथ योजना के प्रथम चरण की आधारशिला रखी गई। परियोजना का क्रियान्वयन आगामी 8 वर्षों में किये जाने का लक्ष्य है। मध्यप्रदेश के इन जिलों को मिलेगा लाभ- पीकेसी परियोजना से प्रदेश के गुना, मुरैना, शिवपुरी, भिंड, श्योपुर, उज्जैन, सीहोर, मंदसौर, इंदौर, देवास, आगरा मालवा, शाजापुर और राजगढ़ जिलों में 22 परियोजनाओं से 3217 गांवों को लाभ मिलेगा। परियोजना के अंतर्गत 17 बांध एवं 4 बैराज समेत 21 जल संरचनाओं का निर्माण किया जाएगा। मालवा और चंबल क्षेत्र की 6.13 लाख हेक्टेयर भूमि हरीभरी हो जाएगी। साथ ही 40 लाख से अधिक आबादी को पेयजल उपलब्ध होगा। पुरानी चंबल दायीं मुख्य नहर एवं वितरण

सीएम छतरपुर में किसान सम्मेलन सह जनकल्याण पर्व में होंगे शामिल

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव गुरुवार 19 दिसंबर 2024 को छतरपुर जिले के स्टार्टेडियम प्रांगण में केन-बेतवा लिंक परियोजना के तहत आयोजित किसान सम्मेलन में शामिल होंगे। उल्लेखनीय है कि 11 से 26 दिसम्बर तक जन-कल्याण पर्व मनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव दोपहर 1 बजे आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में विभिन्न विकास कार्यों का भूमि-पूजन एवं लोकार्पण करेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव दोपहर 3 बजे पन्ना के पॉलिटेक्निक ग्राउण्ड में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। पन्ना में जल-कलश यात्रा, संत सम्मेलन और लोक कल्याण शिविर होंगे।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने समत्व भवन (मुख्यमंत्री निवास) से उज्जैन, सागर, ग्वालियर और चंबल संभाग की समीक्षा बैठक की।

पंजाब के फरीदकोट में पारा 0 डिग्री, राजस्थान के करौली में 1.3 डिग्री

● कश्मीर में झरना जमा, देश के 35 सबसे ठंड़े शहरों में 10 मध्य प्रदेश के

नई दिल्ली/ भोपाल/ जयपुर/ श्रीनगर (एजेंसी)। देश के 8 राज्यों में तापमान में गिरावट जारी है। राजस्थान के करौली में तापमान 1.3 डिग्री पहुंच गया। सीकर, उदयपुर समेत कई जगहों पर गाड़ियों पर बर्फ जम गई। यहां 4-5 दिन तक सड़ी और शीतलहर जारी रहेगी। उधर, पंजाब में भी ठंड का काफी असर है। फरीदकोट में पहली बार रात का पारा 0 डिग्री तक पहुंचा। अबोहर में पारा 0.9 डिग्री रहा। पंजाब के दिन के औसत तापमान में आधा डिग्री की गिरावट आई है। जम्मू-कश्मीर के कई हिस्सों में पारा माइनस से नीचे चल रहा है। श्रीनगर में डल झील सहित कई जलाशय जमने लगे हैं। बारामूला जिले के तंमर्ग में 30 मीटर ऊंचा द्रग झरना ठंड के चलते जम गया है। कश्मीर के श्रीनगर और गुलमर्ग जैसे देश के 35 सबसे ठंडे शहरों में मध्य प्रदेश के भी 10 शहर शामिल हैं। पंचमढ़ी 11वें स्थान पर है। यहां तापमान 1.6 डिग्री तक पहुंच गया है। भोपाल में न्यूनतम तापमान 4 डिग्री दर्ज किया गया। यहां लगातार चौथे दिन शीतलहर चली, जो एक नया रिकॉर्ड है। दिसंबर में इससे पहले लगातार 4 दिन शीतलहर कभी नहीं चली है।

भतीजा बना ‘राक्षस’, बुआ को बना दिया ‘सूर्यनखा’

राजस्थान में जमीन का मसला

जालोर (एजेंसी)। भारत में नाक काटने का जिह्म आते ही रामायण काल की सूर्यनखा का विवरण किया जाता है। लेकिन राजस्थान के जालोर जिले में जमीनी विवाद को लेकर एक भतीजे ने अपनी बुआ की नाक काट देने का हैरान करने वाला कृत्य कर दिया है। उसने अपनी बुआ की चाकू से नाक काट कर अलग कर दिया। इस दौरान चाकू के हमले से पीड़िता बुरी तरह लहलुहान हो गई, जिसे बाद में उपचार के लिए हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। इधर, मामला सामने आने के बाद पुलिस ने तीन लोगों को हिरासत में ले लिया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। हैरान कर देने वाला यह मामला जालोर के सायला थाना क्षेत्र का है, जहां मोकणी गांव में पीड़ित बुआ और भतीजे के बीच जमीनी विवाद सामने आया। जानकारी के अनुसार पीड़ित बुआ कुकी देवी जमीन के मामले को लेकर मोकणी गांव में अपने भाई के पास गईं। बताया जा रहा है कि पीड़ित महिला के प्लाट पर भतीजे ओमप्रकाश ने कब्जा कर रखा था।

दो दिवसीय दौरे पर कुवैत की जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी

43 सालों बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यात्रा होगी

नईदिल्ली (एजेंसी)। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी शनिवार को कुवैत की दो दिवसीय यात्रा पर जाएंगे और किसी भारतीय प्रधानमंत्री को यह 43 वर्षों में इस खाड़ी देश की पहली यात्रा होगी। विदेश मंत्रालय ने इस यात्रा की घोषणा करते हुए कहा कि यह यात्रा भारत और कुवैत के बीच ‘बहुआयामी’ संबंधों को और मजबूत करने का अवसर प्रदान करेगी। मोदी, कुवैत के अमीर शेख मेशाल अल-अहमद अल-जबर अल-सबाह के निमंत्रण पर यह यात्रा कर रहे हैं। यात्रा के दौरान मोदी कुवैत के नेताओं के साथ चर्चा करेंगे और वहां रहने वाले भारतीय समुदाय के साथ भी बातचीत करेंगे। विदेश मंत्रालय का बयान –विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा, “भारत और कुवैत के बीच ऐतिहासिक समय से पारंपरिक रूप से घनिष्ठ तथा मैत्रीपूर्ण संबंध हैं।” इससे पहले, पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 1981 में कुवैत का दौरा किया था। भारत, कुवैत के शीर्ष व्यापारिक साझेदारों में से एक है और भारतीय समुदाय कुवैत में सबसे बड़ा प्रवासी समुदाय है। विदेश मंत्रालय ने कहा, “यह यात्रा भारत और कुवैत के बीच बहुआयामी संबंधों को और मजबूत करने का अवसर प्रदान करेगी। कुवैत, भारत के शीर्ष व्यापारिक साझेदारों में से एक है, जिसका द्विपक्षीय व्यापार वित्तीय वर्ष 2023-24 में 10.47 अरब अमरीकी डॉलर रहा। कुवैत, भारत का छठा सबसे बड़ा कच्चा तेल आपूर्तिकर्ता है, जो देश की ऊर्जा आवश्यकताओं को तीन प्रतिशत तक पूरा करता है। अमीर शेख सबाह अल अहमद अल जाबर अल सबाह जुलाई 2017 में निजी यात्रा पर भारत आए थे। इससे पहले 2013 में कुवैत के प्रधानमंत्री ने भारत की उच्च स्तरीय यात्रा की थी।

बैरसिया में फूड पॉइजनिंग से सात बच्चे बीमार

आंगनबाड़ी में खाया था खाना, 3 से 5 साल उम्र, एक हमीदिया हॉस्पिटल में भर्ती

भोपाल (नप्र)। भोपाल के बैरसिया स्थित इजिरी गांव की आंगनबाड़ी में मिड डे मिल खाने से 7 बच्चे बीमार हो गए। इन सभी की उम्र 3 से 5 साल है। 6 बच्चों को बैरसिया और एक को भोपाल के हमीदिया हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। वहीं, मिड डे मिल खाने वाले



कुल 64 बच्चों की जांच भी कराई गई। बीमार बच्चों ने मिड डे मिल में दाल-रोटी और लप्सी खाई थी। वहीं, पास की माध्यमिक शाला के बच्चों ने दाल-रोटी थी। खाना खाने के कुछ देर बाद ही आंगनबाड़ी केंद्र के बच्चों की तबियत बिगड़ने लगी। जानकारी मिलने पर बैरसिया एसडीएम आशुतोष शर्मा मौके पर पहुंचे और बच्चों की जांच करवाई। इनमें से 7 बच्चों की हालत ठीक नहीं थी। इस कारण सभी को बैरसिया के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रवाना किया गया। इनमें से एक बच्चे को हमीदिया अस्पताल भेजा

गया। कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने बताया, जानकारी लगते ही मौके पर एसडीएम और तहसीलदार को भेजा गया। वहीं, स्वास्थ्य शिविर लगाकर सभी की जांच कराई गई। सभी बच्चों की हालत ठीक है। एहतियातन उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया है।

इन बच्चों की बिगड़ी तबियत: कीर्तिका पिता शिवनारायण उम्र 4 वर्ष, नायरा पिता उधम सिंह उम्र 3 वर्ष, वैशाली पिता भैयालाल उम्र 4 वर्ष, विराट पिता रमेश उम्र 5 वर्ष, परी पिता धर्मेन्द्र उम्र 5 वर्ष, प्रिंस पिता धर्मेन्द्र उम्र 4 वर्ष और ऋभ पिता विनोद उम्र 4 वर्ष। इनमें से प्रिंस को हमीदिया अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तहसीलदार करुणा दंडोतिया ने बताया कि सैपल जांच के लिए भेजे गए हैं। जांच रिपोर्ट आने के बाद ही स्थिति साफ होगी।

उल्टी-दस्त की शिकायत होने लगी: इस आंगनबाड़ी में बालाजी स्व सहायता समूह द्वारा मिड डे मिल यानी, पौष्टिक आहार वितरण किया गया था। दोपहर 3.30 बजे बच्चों को उल्टी एवं दस्त की शिकायत होने लगी।

भोपाल की युवती के साथ लव जिहाद, एफआईआर

शादी का झांसा देकर राहुल बनकर समीर ने किया रेप; कहता था-धर्म बदल दो

भोपाल (नप्र)। भोपाल के कोलार इलाके में रहने वाली युवती के साथ लव जिहाद का मामला सामने आया है। एक युवक ने नाम बदलकर उससे मुलाकात की। शादी का झांसा देकर संबंध बनाए, पिछले दिनों शादी के नाम पर लड़की को इस्लाम धर्म अपनाने का दबाव डाला। पीड़िता के इनकार करने पर आरोपी ने उससे रिश्ता तोड़ लिया। जिसके बाद बुधवार पीड़िता 'संस्कृति बचाओ' मंच के कार्यकर्ताओं को लेकर थाना पहुंची, शिकायत पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। कोलार थाना टीआई संजय सिंह सोनी ने बताया किधार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम, रेप, एससी-एसटी एक्ट सहित धमकाने की धाराओं में एफआईआर दर्ज की है। घटना पहली बार जहांगीराबाद इलाके में हुई, लिहाजा केस डायरी को ट्रान्सफर किया जाएगा। 25 वर्षीय युवती प्राइवेट जॉब करती है। चार साल पहले अनजान नंबर से उसे कॉल आना शुरू हुए थे। कॉल करने वाले ने खुद को राहुल बताया था, बाद में युवक वाट्सएप मैसेज करने लगा। उसने लड़की को दोस्ती के लिए राजी कर लिया। कुछ समय में दोनों की मुलाकात हुई। इसके बाद आरोपी और



पीड़िता की कॉल पर बातें चलती रहीं। आरोपी ने उसे इजहार किया, लड़की ने हां कर दिया। तब तक उसे जानकारी नहीं थी कि जिसे वह राहुल समझ रही है, असल में वह साहिल खान है और जहांगीराबाद इलाके का रहने वाला है। आरोपी ने लड़की को मिलने बुलाया। जहांगीराबाद इलाके के एक कमरे में उसके साथ संबंध बनाए और शादी का झांसा दिया। क्योंकि पीड़िता को भरोसा था कि आरोपी उससे शादी करेगा तो लड़की ने विरोध नहीं किया। एक दिन लड़की को उसकी सच्चाई पता लगी।

ऑक्सीजन पाइप काटा, बारह नवजात की जान खतरे में पड़ी

सांस लेने में दिक्कत हुई तो रोने लगे; राजगढ़ में डॉक्टरों ने जबो सिलेंडर से बचाई जान



राजगढ़ (नप्र)। राजगढ़ जिला अस्पताल में भर्ती 12 नवजातों की जान उस वक्त खतरे में पड़ गई, जब चोर वार्ड में ऑक्सीजन सप्लाई की पाइपलाइन काट ले गए। घटना के वक्त एनआईसी (नवजात शिशु गहन चिकित्सा इकाई) में 20 बच्चे भर्ती थे। इनमें से 12 ऑक्सीजन सप्लाई पर थे। घटना मंगलवार रात की है। जैसे ही इसकी जानकारी मेडिकल स्टाफ को लगी, उन्होंने सीनियर डॉक्टर को सूचना दी। जानकारी मिलने पर शिशु रोग विशेषज्ञ डॉ. आरएस माथुर हॉस्पिटल पहुंचे। ऑक्सीजन यूनित की ओर गए तो पाइपलाइन कटी दिखी। इसके बाद अस्पताल में ही रखे जबो सिलेंडर से बच्चों को ऑक्सीजन सप्लाई की गई।

सप्लाई बंद होने पर बच्चे रोये, अलार्म बजा: पोस्टमार्टम रूम के पास ऑक्सीजन सिलेंडर की कोपर की पाइपलाइन करीब 10 से 15 फीट तक कटी हुई थी। मंगलवार देर रात अज्ञात चोरों ने इस पाइपलाइन को काटकर चुरा लिया। पाइपलाइन कटने के कारण एनआईसीयू वार्ड में भर्ती बच्चों के लिए ऑक्सीजन की सप्लाई बंद हो गई थी। इससे बच्चे रोने लगे और अस्पताल में अलार्म भी बजने लगा। अस्पताल स्टाफ ने तुरंत डॉक्टरों को सूचना दी और एनआईसीयू वार्ड के बाहर लगे इमरजेंसी जबो ऑक्सीजन सिलेंडर से ऑक्सीजन की आपूर्ति शुरू की। इससे एनआईसी वार्ड में भर्ती बच्चों की किसी बड़ी दुर्घटना से बचा लिया गया।

हमीदिया से 400 कर्मचारियों को निकालने की तैयारी

जीएमसी के पास पैसा नहीं, इसलिए वार्ड बॉय की सैलरी में दिक्कत

भोपाल (नप्र)। हमीदिया अस्पताल के मैनेजमेंट ने 400 कर्मचारियों को निकालने की तैयारी कर ली है। ये कौन से कर्मचारी होंगे, अभी तय नहीं है। इसे लेकर मैनेजमेंट ने निजी कंपनी को लेटर जारी किया है। बताया जा रहा है कि ये वे कर्मचारी हो सकते हैं, जिनकी जॉइनिंग कोविड के दौरान हुई थी। जीएमसी (गांधी मेडिकल कॉलेज) का कहना है कि शासन से सैक्शन पदों के मुकाबले हमीदिया में 400 कर्मचारी अधिक काम कर रहे हैं। वर्तमान में शासन की ओर से जितने पद सैक्शन हैं, उस आधार पर निर्णय लिया जाएगा। उधर, हमीदिया अस्पताल में वार्ड बॉय, कंप्यूटर ऑपरेटर और हाउस कीपिंग स्टाफ मंगलवार सुबह से हड़ताल पर चले गए। जीएमसी की डीन डॉ. कविता एन सिंह का कहना है-इनकी सैलरी शुक्रवार या शनिवार तक आ जाएगी। सैलरी में देरी की वजह पैसा नहीं होना है।सैलरी के लिए हमीदिया अस्पताल के 500 से अधिक वार्ड बॉय और अन्य कर्मचारी



15 दिन में दो बार हड़ताल पर बैठ चुके वार्ड बॉय सैलरी के लिए हमीदिया अस्पताल के 500 से अधिक वार्ड बॉय करीब 15 दिन में दो बार हड़ताल पर बैठ चुके हैं। बता दें, हमीदिया अस्पताल में रोज 2500 से अधिक की ओपीडी (आउटपैशेंट डिपार्टमेंट) रहती है। 60 से अधिक ऑपरेशन होते हैं।

सैलरी के लिए मिले 2.5 करोड़ रुपए गांधी मेडिकल कॉलेज ने एजाइल कंपनी को दो दिन पहले करीब द्वाई करोड़ रुपए का पैमेंट किया है। इसके बाद करीब 12 करोड़ रुपए जीएमसी पर बकाया है। इस वजह से कंपनी ने कर्मचारियों की सैलरी रोक दी है। दो महीने पहले कर्मचारियों की हड़ताल के बाद कंपनी को 1 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया था। हालांकि, तब दिवाली बोनस नहीं दिया गया था। इससे पहले इन कर्मचारियों ने तीन से चार बार कंपनी को पत्र लिखकर शिकायत की थी। पत्र के जवाब में कंपनी ने सिर्फ आश्वासन दिया था हमीदिया अस्पताल में रोज 2500 से अधिक की ओपीडी रहती है। 60 से अधिक ऑपरेशन होते हैं।

एमपी में 2 साल में साइबर फ्रॉड के 992 केस, 152 करोड़ रुपए ठगी

2023 की तुलना में ठगों की पैसे उड़ाने की स्पीड 80 प्रतिशत बढ़ी

भोपाल (नप्र)। डिजिटल अरेस्ट और साइबर फ्रॉड के मामले सरकार और समाज दोनों के लिए चिंता का विषय बनते जा रहे हैं। ठग नए-नए तरीके अपनाकर लोगों की मेहनत की कमाई चंद मिनटों में उड़ा देते हैं। पिछले दो साल में मध्यप्रदेश में साइबर फ्रॉड के 992 मामले सामने आए हैं। ठगों ने लगभग 152 करोड़ रुपए की ठगी की है। कांग्रेस विधायक प्रताप ग्रेवाल के सवाल के जवाब में विधानसभा में यह जानकारी सामने आई है।

साल भर में ठगी की राशि में 80 प्रतिशत का इजाफा: गृह विभाग की जानकारी के मुताबिक, 2023 में ऑनलाइन ठगी के भोपाल में 53, इंदौर में 184 मामले सामने आए। पूरे मध्यप्रदेश में साल 2023 में 444 मामलों में 19 करोड़ रुपए की ठगी हुई। इस साल 2024 में ठगी की राशि बढ़कर 94 करोड़ हो गई। 2024 में भोपाल में 77, इंदौर में 141, जबलपुर में 94, उज्जैन में 44 मिलाकर प्रदेश में कुल 521 मामले सामने आए। ऑनलाइन ठगी के



मामलों में 2023 की तुलना में 2024 में 20 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई, लेकिन ठगी की राशि पांच गुना ज्यादा बढ़ी है।

510 साइबर अपराधी गिरफ्तार: मध्यप्रदेश में 2023 और 2024 में ऑनलाइन ठगी के 965 मामलों में 138 करोड़ और डिजिटल अरेस्ट के 27 मामलों में 14 करोड़ रुपए की ठगी हुई। गृह विभाग के अफसरों ने बताया कि साइबर अपराधियों से 18 करोड़ रुपए की राशि जब्त की गई है। 510 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। ज्यादातर मामलों में पुलिस, बैंक, आयकर विभाग, सीबीआई, कस्टम, ट्राई के अधिकारी बनकर लोगों से ठगी की गई थी।

अफसरों पर अभियोजन अनुमति पेंडिंग केस की जानकारी मांगी

सरकार का जवाब- अधिकारियों की जानकारी मांगी, शासकीय सेवक की नहीं; इसलिए बता नहीं सकते

भोपाल (नप्र)। प्रदेश में ब्यूरोक्रेट्स के विरुद्ध करणन और शासकीय नियमों की अवहेलना के मामले में लोकायुक्त द्वारा की जाने वाली जांच और उनके विरुद्ध कार्रवाई के लिए अभियोजन स्वीकृति के मामले में जानकारी न देने सरकार ने नया तरीका खोजा है। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंधार ने इसको लेकर सरकार से जानकारी मांगी तो सरकार ने लिखित तौर पर यह कहकर जानकारी देने से इनकार कर दिया कि विधायक ने अधिकारियों के अभियोजना के संबंध में जानकारी मांगी है,

शासकीय पत्राचार में अधिकारी शब्द का इस्तेमाल नहीं होता बल्कि शासकीय सेवक लिखा जाता है, इसलिए जानकारी नहीं दी जा सकती। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष सिंधार ने विधानसभा के जरिए सरकार से पूछा था कि, लोकायुक्त संगठन द्वारा कुल कितने अधिकारियों के विरुद्ध अभियोजन की स्वीकृति सरकार से मांगी गई है। सरकार से यह भी पूछा गया था कि 2019 से 2024 के बीच कुल कितने मामलों में स्वीकृति दी गई है और किस तरह के प्रकरणों में नहीं दी गई है? जिन प्रकरणों में स्वीकृति

दी है, क्या उनके मामले न्यायालय में पेश हो गए हैं? इसके साथ ही यह भी पूछा गया है कि जिनके मामले में स्वीकृति नहीं दी गई है, उसके नियम के बारे में जानकारी दी जाए।

सरकार ने यह जवाब दिया है: नेता प्रतिपक्ष के सवाल के लिखित जवाब में मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव की ओर से बताया गया है कि सामान्य प्रशासन विभाग के 1 नवम्बर 2014 के परिपत्र के अनुसार शासकीय प्रशासकीय व्यवहार में अधिकारी-कर्मचारी का संबंधोन समाप्त कर दिया गया है।

पुष्पा-2 दिखाकर गला घोंटा, पत्थर से कुचल दिया

लाश दफनाकर नमक डाला; यूट्यूब से सीखा था बॉडी गलाने का तरीका



दोबारा कॉल किया तो फोन बंद आ रहा था। रात तक ऋषि घर नहीं पहुंचा तो परिवार वालों ने तलाश शुरू की। 8 दिसंबर को मोतीनगर थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई। पुलिस ने ऋषि के मोबाइल नंबर की कॉल डिटेल निकलवाई। इसके आधार पर 10 दिसंबर की रात रेलवे स्टेशन के पास एक संदिग्ध को पकड़ा। थाने लाकर पूछताछ की। पूछताछ में आरोपी ने ऋषि

की हत्या किए जाने की बात कबूल ली। पुलिस रात में ही वारदात स्थल पर पहुंची और छनबीन की। यहां शव होने की पुष्टि हुई। 11 दिसंबर को पुलिस ने शव बरामद कर लिया।पुलिस आरोपी गोलू पटेल को वारदात स्थल पर लेकर पर पहुंची और शव की निशानदेही कराई।

30 हजार रुपए लौटाने से कर दिया था इनकार: ऋषि अहिरवार की जानकारी गोलू उर्फ बलराम पिता दिनेश पटेल निवासी पंतनगर अच्छे दोस्त थे। दोनों अटो चलाकर परिवार पाल रहे थे। करीब 5 महीने पहले ऋषि ने गोलू से 30 हजार रुपए उधार लिए थे। गोलू ने अपनी पिकअप बेचकर ऋषि को रुपए दिए थे। गोलू अपने पैसे वापस मांग रहा था लेकिन ऋषि लगातार टाल रहा था। वारदात से करीब एक सप्ताह पहले गोलू

कुएं में मिला नव विवाहिता का शव

पति से झगड़ा होने के बाद हुई थी लापता पुलिस ने की जांच शुरू



लाइट से कुएं में सच किया तो महिला की लाश नजर आई। आस पड़ोस के लोगों सहित उसने पुलिस को सूचना दी। इसके बाद शव को कुएं से बाहर निकाला गया।

पति पर झगड़ा करने के आरोप

मुक्तिका के मामा मदन ने बताया कि प्रीति का पति शराब पीने का आदि था। नशे में धुत होकर पत्नी से आए दिन विवाद करता था। सोमवार को भी आरोपी ने विवाद किया, जिसके बाद गुस्से में प्रीति घर से निकली थी और मंगलवार को उसका शव मिला है।

आबकारी नीति के निर्धारण के लिये मंत्रि-परिषद समिति का गठन

भोपाल (नप्र)। राज्य शासन द्वारा वर्ष 2025-26 के लिये आबकारी नीति के निर्धारण एवं समय-समय पर अनुषांगिक विषयों पर निर्णय लेने के लिये मंत्रि-परिषद समिति का गठन किया गया है। समिति में उप मुख्यमंत्री श्री जगदीश देवड़ा, परिवहन एवं स्कूल शिक्षा मंत्री श्री उदय प्रताप सिंह, महिला-बाल विकास मंत्री सुश्री निर्मला भूरिया और खाद्य, नगरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री श्री गोविन्द सिंह राजपूत को मनोनीत किया गया है। प्रमुख सचिव वाणिज्य कर समिति के सचिव होंगे।

ने एक बार फिर रुपए लौटाने की बात कही तो ऋषि ने देने से मना कर दिया। गालीगलौज भी की। उसने कहा, पैसे नहीं दूंगा। जो करना है, कर लेना। बात गोलू को लग गई। उसने ऋषि को सक्के सिखाने की प्लानिंग की। इसमें 13 वर्षीय नाबालिग को भी शामिल कर लिया।

रस्सी फंसाकर गिराया, फिर पत्थर पटक दिया: गोलू ने पुलिस को बताया, 7 दिसंबर को ऋषि को शराब पार्टी करने के बहाने मंगलगिरी इलाके में पहाड़ी पर बुलाया। दोपहर करीब 12 बजे मैं और नाबालिग दोस्त पहाड़ी पर पहुंचे। कुछ देर में ऋषि भी आ गया। तीनों ने बैठकर शराब पी। जिसके बाद ऋषि का ध्यान भटकाने के लिए मोबाइल पर पुष्पा-2 मूवी लगाई। मोबाइल उसे थमाकर मैं उसके पीछे बैठ गया। मैं कपड़ों में छिपाकर रस्सी साथ ले गया। उसे उठाकर ऋषि के गले में फंसाया और ज़ोरदार झटका मारा। इस झटके से हम दोनों जमीन पर गिर गए।

संपादकीय

उम्मीद से भरा त्रिपक्षीय करार

महत्वाकांक्षी ‘पार्वती- कालीसिंध- चंबल नदी जोड़ो परियोजना’ पर जयपुर में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की मौजूदगी में त्रिपक्षीय अनुबध पर हस्ताक्षर होना मप्र और खासकर मालवा चंबल क्षेत्र के विकास की दृष्टि से स्वागतय कदम है। यह अनुबंध मप्र और राजस्थान राज्यों के बीच हुआ है, जहां दोनों जगह भाजपा की सरकारें हैं, इसलिए यह उम्मीद की जाती चाहिए कि इस परियोजना पर तेजी से काम होगा और जल्द से लीगों को इसका लाभ मिलेगा। केन्द्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस पहल का स्वागत करते हुए कहा कि यह परियोजना ग्वालियर चंबल व मालवा क्षेत्र के लिए ऐतिहासिक सौगात है। इस समूची परियोजना पर 72 हजार करोड़ रू. की ज्यादा कृषि भूमि में सिंचाई हो सकेगी। साथ ही 40 लाख से अधिक आबादी को पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा। मध्यप्रदेश के मालवा और चंबल के क्षेत्र के लाखों किसान इस परियोजना के माध्यम से लाभ ले सकेंगे। परियोजना का भूमिपूजन राजस्थान के टोंक खुर्द कृषि मंडी परिसर में सम्पन्न हुआ। इस परियोजना से गुना, शिवपुरी, सीहोर, देवास, राजगढ़, उज्जैन, आगरा मालवा, इंदौर, शाजापुर, मंदसौर और मुरैना के 2094 गांव लाभान्वित होंगे। योजना के अंतर्गत मध्यप्रदेश में 21 बांध एवं बैराज बनाए जाएंगे। मप्र में लगभग 36 हजार 800 करोड़ रुपए से कार्य करवाए जाएंगे। इस परियोजना के बारे में मप्र के जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिसावट ने बताया, एमपी में 35 हजार करोड़ रुपए और राजस्थान में 37 हजार करोड़ के काम होंगे। 90 फीसदी राशि केंद्र व 10 प्रतिशत राज्य सरकार देगी। इसमें शक नहीं कि मप्र में भाजपा के 20 साल के शासन काल में सिंचाई क्षमता के विकास और विस्तार पर काफी ध्यान दिया गया है। आज राज्य में सिंचित कृषि क्षेत्र 169.48 लाख हेक्टेयर तक जा पहुंचा है। पार्वती-कालीसिंध-चंबल लिंक परियोजना इस में और वृद्धि करेगी। यही कारण है कि आज मप्र देश के पांच अग्रणी कृषि राज्यों में शामिल हो गया है। कुछ फसलों के उत्पादन में तो हम देश में नंबर वन हो चुके हैं। लेकिन उपलब्धियों के साथ साथ सरकार और प्रदेश के समक्ष कई नई चुनौतियां भी खड़ी हो गई हैं। जिस तेजी से राज्य में कृषि उत्पादन बढ़ा है, उस तेजी से न तो फसलों के दामों में बढ़ोतरी हुई है और न ही भंडारण व खाद्य प्रसंस्करण उद्योग बढ़े हैं। मप्र का कच्चा माल राज्य में ही प्रोसेस हो, इस बारे में बहुत कम प्रगति हो सकी है। बेहतर भावों के लिए किसानों को अभी भी या तो दूसरे राज्यों का रूख करना पड़ता है या फिर अपने पौने दामों पर फसल बेचकर घाटा उठकर खेती करना पड़ती है। खेती को लाभ का धंधा बनाने और खुद को किसान का बेटा कहने वाले मप्र के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान ने भी मीडिया से बातचीत के दौरान माना था कि कृषि उत्पादन वृद्धि के मामले में हमारे किसानों ने जो कमाल किया है, उस तुलना में उपज के भंडारण और प्रसंस्करण के मामले में हम आगे नहीं बढ़ सके हैं। पार्वती कालीसिंध चंबल लिंक परियोजना इसमें कितनी मददगार होती है, यह देखने की बात है। औद्योगिकरण के मामले में मप्र पड़ोसी राज्यों की तुलना में अभी भी पीछे है। लिहाजा हमे कृषि पर ही और ज्यादा ध्यान देना होगा। मप्र में रोजगार का सबसे बड़ा क्षेत्र अभी भी यही है। ऐसे में पार्वती कालीसिंध चंबल लिंक जैसी परियोजनाओं की हमे और आवश्यकता है। लेकिन पर्यावरण बचाने का भी ध्यान रखना होगा। इसी तरह केन बेतवा परियोजना भी तेजी से आगे बढ़ने की राह देख रही है।

नजरिया

प्रमोद भार्गव

लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं।

मध्यप्रदेश और राजस्थान के बीच पार्वती, कालीसिंध और चंबल का पानी एक बड़े जलस्रोत के रूप में बहता है। मध्यप्रदेश में केन-बेतवा नदी जोड़ो परियोजना की शुरूआत के बाद अब उपरोक्त नदियों को जोड़े जाने की आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जयपुर में रख दी है। इसके प्रतीक स्वरूप तीनों नदियों के पानी को एक घड़े में भरा गया। तत्पश्चात भारत सरकार और राजस्थान एवं मध्यप्रदेश राज्य सरकारों के बीच एक त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। 72000 करोड़ रुपए इस परियोजना पर खर्च होंगे। इसमें 90 प्रतिशत राशि केंद्र सरकार देगी। इस राशि में से 35000 करोड़ रुपए मध्यप्रदेश और 37000 करोड़ रुपए राजस्थान सरकार खर्च करेगी। इसमें मध्यप्रदेश के 13 जिलों के 3217 ग्रामों की सूरत बदल जाएगी। दोनों प्रदेशों में मिलाकर 27 नए बांध बनेंगे और 4 पुराने बांधों पर नहरों की जलग्रहण क्षमता बढ़ाई जाएगी। इसी के साथ 64 साल पुरानी ग्वालियर-चंबल संभाग की चंबल-नहर प्रणाली का उद्धार नए तरीके से किया जाएगा। तय है, ये नदियां निर्धारित अवधि में जुड़ जाती हैं, तो सिंचाई के लिए कृषि भूमि का रकबा बढ़ने के साथ अन्न की पैदावार बढ़ेगी। किसान खुशहाल होंगे और उनके जीवन स्तर में सुधार आएगा।

नदियों की धारा मोड़ने का दुनिया में पहला उदाहरण ऋग्वेद में मिलता है। इंद्र ने सिंचाई और पेयजल की सुविधा सुगम कराने की दृष्टि से सिंधु नदी की धारा को मोड़ा था। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी की धारा को पहाड़ तोड़कर भगवान परशुराम ने मोड़ा था। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपयी ने नदी जोड़ो अभियान की जो परिकल्पना की थी, उसे नरेंद्र मोदी ने साकार करने की शुरूआत केन-बेतवा नदी जोड़ो परियोजना के साथ कर दी थी। ये परियोजनाएं जल-शक्ति अभियान ‘केच द रन’ के तहत अमल में लाई जा रही हैं। बाढ़ और सूखे से परेशान देश में नदियों के संगम की परियोजना मूल रूप ले रही है, यह देशवासियों के लिए प्रसन्नता की बात है। इन परियोजनाओं को जोड़ने का अभियान सफल होता है तो भविष्य में 57 अन्य नदियों के मिलन का रास्ता खुल जाएगा। दरअसल बढ़ते वैश्विक तापमान, जलवायु परिवर्तन और बदलते वर्षा-चक्र के चलते जरूरी हो गया है कि नदियों के बाढ़ के पानी को इकट्ठा किया जाए और फिर उसे सूखाग्रस्त क्षेत्रों में नहरों के जरिए भेजा जाए। ऐसा संभव हो जाता है तो पेयजल की समस्या का निदान तो होगा ही, सिंचाई

वागर्थ

नदियां लिखेंगी विकास की गाथा

के लिए भी किसानों को पर्याप्त जल मिलने लग जाएगा। वैसे भी भारत में विश्व की कुल आबादी के करीब 18 प्रतिशत लोग रहते हैं और उपयोगी जल की उपलब्धता महज 4 प्रतिशत है। हालांकि पर्यावरणविद् इन परियोजनाओं को यह कहकर विरोध कर रहे हैं कि नदियों को जोड़ने से इनकी अतिरलता खत्म होगी, नतीजतन नदियों के विलुप्त होने का संकट बढ़ जाएगा। कृत्रिम रूप से जीवनदायी नर्मदा और मोक्षदायिनी



क्षिप्रा नदियों को जोड़ने का काम मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहले ही कर चुके थे। चूँकि ये दोनों नदियां मध्य-प्रदेश में बहती थीं, इसलिए इन्हें जोड़ा जाना संभव हो गया था। केन और बेतवा नदियों को जोड़ने की तैयारी में मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सरकारें बहुत पहले से जुटी थीं। इस परियोजना को वर्ष 2005 में मंजूरी भी मिल गई थी, लेकिन पानी के बंटवारे को लेकर विवाद बना हुआ था। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि दोनों राज्यों में अलग-अलग दलों की सरकारें होने के कारण एकमत नहीं हुई। कालांतर में केंद्र समेत उग्र और मप्र में भी भाजपा की सरकारें बन आईं। नतीजतन परियोजनाओं पर सहमति बन गई। केन नदी जबलपुर के पास कैमूर की पहाड़ियों से निकलकर 427 किमी उत्तर की ओर बहने के बाद बांदा जिले में यमुना नदी में जाकर गिरती है। वहीं बेतवा नदी मध्य-प्रदेश के रायसेन जिले से निकलकर 576 किमी बहने के बाद उत्तर-प्रदेश के हमीरपुर में यमुना में मिलती है। केन-बेतवा नदी जोड़ो योजना पर भूमि अधिग्रहण के साथ

तेज गति से बांधों एवं नहरों का काम शुरू हो गया है। जीवनदायी नदियां हमारी सांस्कृतिक धरोहर हैं। नदियों के किनारे ही ऐसी आधुनिकतम बड़ी सभ्यताएं विकसित हुईं, जिन पर हम गर्व कर सकते हैं। सिंधु घाटी और सारस्वत (सरस्वती) सभ्यताएं इसके उदाहरण हैं। भारत के सांस्कृतिक उन्नयन के नायकों में भारीरथी, राम और कृष्ण का नदियों से गहरा संबंध रहा है। भारतीय वांगमय में इंद्र और कुबेर विपुल जलराशि के प्राचीनतम

पर्यावरण संस्था ने मरी हुई नदी तक घोषित कर दिया है। प्रस्तावित करीब 120 अरब डालर अनुमानित खर्च की नदी जोड़ें परियोजना को दो हिस्सों में बांटकर अमल में लाया जाएगा। एक प्रायद्वीप स्थित नदियों को जोड़ना और दूसरे, हिमालय से निकली नदियों को जोड़ना। प्रायद्वीप भाग में 16 नदियां हैं, जिन्हें दक्षिण जल क्षेत्र बनाकर जोड़ा जाना है। इसमें महानदी, गोदावरी, पेनारा, कृष्णा, पार, तापी, नर्मदा, दमनगंगा, पिंजाल और कावेरी को जोड़ा जाएगा। पश्चिम के तटीय हिस्से में बहने वाली नदियों को पूर्व की ओर मोड़ा जाएगा। इस तट से जुड़ी तापी नदी के दक्षिण भाग को मुंबई के उत्तरी भाग की नदियों से जोड़ा जाना प्रस्तावित है। केरल और कर्नाटक की पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों की जलधारा पूर्व दिशा में मोड़ी जाएगी। यमुना और दक्षिण की सहायक नदियों को भी आपस में जोड़ा जाना इस परियोजना का हिस्सा है। हिमालय क्षेत्र की नदियों के अतिरिक्त जल को संग्रह करने की दृष्टि से भारत और नेपाल में गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र तथा इनकी सहायक नदियों पर विशाल जलाशय बनाने के प्रावधान हैं। ताकि वर्षाजल इकट्ठा हो और उत्तर-प्रदेश, बिहार एवं असम को भंयकर बाढ़ का सामना करने से छुटकारा मिले। इन जलाशयों से बिजली भी उत्पादित की जाएगी। इसी क्षेत्र में कोसी, घाघरा, मेघ, गंडक, साबरमती, शारदा, फरक्का, सुन्दरवन, स्वर्णरेखा और दमोदर नदियों को गंगा, यमुना और महानदी से जोड़ा जाएगा। करीब 13,500 किमी लंबी ये नदियां भारत के संपूर्ण मैदानी क्षेत्रों में अठखेलियां करती हुई मनुष्य और जीव-जगत के लिए प्रकृति का अनूठा और बहुमूल्य वरदान बनी हुई हैं। 2528 लाख हेक्टेयर भू-खण्डों और वनप्रतारों में प्रवाहित इन नदियों में प्रति व्यक्ति 690 घनमीटर जल है। कृषि योग्य नदियों 1411 लाख हेक्टेयर भूमि में से 546 लाख हेक्टेयर भूमि इन्हीं नदियों की बढौलत प्रति वर्ष सिंचित की जाकर फसलों को लहलहाती है।

दरअसल बढ़ते वैश्विक तापमान, जलवायु परिवर्तन, अलनीनो और बदलते वर्षा चक्र के चलते जरूरी हो गया है कि नदियों के बाढ़ के पानी को इकट्ठा किया जाए और फिर उसे सूखाग्रस्त क्षेत्रों में नहरों के जरिए भेजा जाए। ऐसा संभव हो जाता है तो पेयजल की समस्या का निदान तो होगा ही, सिंचाई के लिए भी किसानों को पर्याप्त जल मिलने लग जाएगा। वैसे भी भारत में विश्व की कुल आबादी के करीब 18 प्रतिशत लोग रहते हैं और उपयोगी जल की उपलब्धता महज 4 प्रतिशत है। इसलिए नदी जोड़ो परियोजनाओं को भविष्य के लिए लाभदायी माना जा रहा है।

मुद्दा

आरके सिन्हा

लेखक पूर्व सांसद हैं।

‘एक देश एक चुनाव’ के सपने को साकार करने की तरफ देश बढ़ रहा है। बेशक,लगातार चुनाव देश की प्रगति में बाधा बन रहे हैं। भारत में ‘एक देश-एक चुनाव’ का विचार एक ऐसा विषय है जिस पर अलग-अलग लोगों की अलग-अलग राय है। कुछ लोगों का मानना है कि इससे देश को कई फायदे होंगे, वहीं कुछ लोग इसके कुछ नुकसान भी बताते हैं। पर ये सच है कि बार-बार चुनाव कराने में काफी पैसा खर्च होता है। एक साथ चुनाव कराने से इस खर्च को काफी ह्राद थे कम किया जा सके । चुनावों में सरकारी कर्मचारियों और सुरक्षा बलों की भारी संख्या में तैनाती करनी पड़ती है। जाहिर है, बार-बार चुनाव होने से कामकाज में बाधा तो आती ही है साथ ही संसाधनों का भारी दुरुपयोग भी होता है। एक साथ चुनाव कराने से इस समस्या को दूर काफी हद तक कम किया जा सकता है। पूर्व राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिशों के बाद सरकार एक देश- एक चुनाव की तरफ तेजी से बढ़ रही है। इससे लोकसभा, विधानसभा, नगर निकाय और पंचायत चुनाव सभी एक साथ होंगे। यह सब 100 दिनों के अंदर ही संपन्न होगा। सरकार का मानना है कि इससे देश की जीडीपी में 1-1.5 प्रतिशत की वृद्धि होगी। केंद्र सरकार इस मुद्दे पर आम सहमति बनाना चाहती है। यह मामला किसी एक दल का

स्वामी, सुबह सवेरे मीडिया एल.एल.पी. के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक उमेश त्रिवेदी द्वारा श्री सिद्धिविनायक प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 26-बी, देशबंधु परिसर, प्रेस कॉम्पलेक्स, जोन-1, एम.पी.नगर, भोपाल, म.प्र. से मुद्रित एवं डी-100/46, शिवाजी नगर भोपाल से प्रकाशित।

प्रधान संपादक

उमेश त्रिवेदी

कार्यकारी प्रधान संपादक

अजय बोकिल

संपादक (मध्यप्रदेश)

विनोद तिवारी

वरिष्ठ संपादक

पंकज शुक्ला

प्रबंध संपादक

अरुण पटेल

(सभी विवादों का न्याय क्षेत्र भोपाल रहेगा)

RNI No. MPHIN/ 2003/ 10923,

Ph. No. 0755-2422692, 4059111

Email- subahsaverenews@gmail.com

‘सुबह सवेरे’ में प्रकाशित विचार लेखकों के निजी मत हैं। इनसे सम्पादक पत्र का सम्बन्ध होना आवश्यक नहीं है।

क्या कमी है ‘एक देश एक चुनाव’ में?

नहीं, बल्कि पूरे देश के हित में है। यह सबको पता है कि देश में बार-बार चुनाव होने से जनता और सरकारी अधिकारियों का समय और संसाधन बर्बाद होता है। एक साथ चुनाव कराने से यह सब नहीं होगा। एक साथ चुनाव होने से राजनीतिक स्थिरता में सुधार आएगा, क्योंकि सरकार को बार-बार चुनावों की चिंता नहीं



करनी पड़ेगी। इसके साथ ही एक साथ चुनाव होने से प्रशासन पर दबाव कम होगा और वे अपने काम पर अधिक ध्यान केंद्रित कर पाएंगे। तो आप कह सकते हैं कि ‘एक देश, एक चुनाव’ से कई मसलों का हल हो जाएगा। चुनावों की अवधि कम हो जाने से, शासन और विकास कार्यक्रमों पर ध्यान केंद्रित किया जा सकेगा।

एक देश, एक चुनाव भाजपा और नरेंद्र मोदी का पुराना एजेंडा है। प्रधानमंत्री बनने के बाद से ही मोदी जी इसकी वकालत करते रहे हैं। अपने दूसरे कार्यकाल में 2 सितंबर 2023 को कोविंद कमिटी बना कर उन्होंने पहला कदम बढ़ाया था। निश्चित रूप से बार-बार चुनाव होने से सरकारें नई नीतियों और योजनाओं को लागू करने में झिझकती हैं। एक साथ चुनाव होने से सरकारों को स्थिरता मिलती है और वे बेहतर ढंग से काम कर पाती हैं। एक बात

और कि बार-बार चुनाव होने से राजनीतिक दल विकास के मुद्दों से भटक जाते हैं और चुनाव जीतने पर ही ध्यान केंद्रित करते हैं। एक साथ चुनाव होने से राजनीतिक दलों को विकास पर ध्यान केंद्रित करने का अधिक अवसर मिलता है।

‘एक देश-एक चुनाव’ के विपक्ष में तर्क में कुछ पिलपिले तर्क आ रहे हैं। जैसे कि

लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए चुनाव एक साथ ही होते थे। साल 1947 में आज़ादी के बाद भारत में नए संविधान के तहत देश में पहला आम चुनाव साल 1952 में हुआ था। उस समय राज्य विधानसभाओं के लिए भी चुनाव साथ ही कराए गए थे, क्योंकि आज़ादी के बाद विधानसभा के लिए पहली बार चुनाव हो रहे थे। उसके बाद साल 1957, 1962 और 1967 में भी लोकसभा और विधानसभा के चुनाव साथ ही हुए थे। यह सिलसिला पहली बार उस वक़्त टूटा था जब केरल में साल 1957 के चुनाव में ईएमएस नंबूदरीबाद की वामपंथी सरकार बनी। साल 1967 के बाद कुछ राज्यों की विधानसभा जल्दी भंग हो गई और वहां राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया, इसके अलावा साल 1972 में होनेवाले लोकसभा चुनाव भी समय से पहले कराए गए थे। साल 1967 के चुनावों में कांग्रेस को कई राज्यों में विधानसभा चुनावों में हार का सामना करना पड़ा था। बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, पश्चिम बंगाल और ओडिशा जैसे कई राज्यों में विरोधी दलों या गठबंधन की सरकार बनी थी। इनमें से कई सरकारें अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाईं और विधानसभा समय से पहले भंग हो गई थी। यह भी माना जा रहा है कि एक साथ चुनाव होने से मतदाता भागीदारी में वृद्धि हो सकती है क्योंकि लोगों को बार-बार मतदान करने की आवश्यकता नहीं होगी। कुल मिलाकर बात यह है कि ‘एक देश एक चुनाव’ को दलागत आधार पर नहीं देखा जाना चाहिए। इस पर हर स्तर पर खुल कर ईमानदारी से चर्चा होनी चाहिए। उसके बाद ही किसी अंतिम निर्णय पर पहुंचा जाना चाहिए। अगर इसे भाजपा या मोदी जी के किसी एजेंडे के रूप में देखा गया तो यह सही नहीं होगा। अभी तक जो विपक्षी नेता ‘एक देश एक चुनाव’ के विचार का विरोध कर रहे हैं, उन्हें अपने दिल पर हाथ रखकर पूछना चाहिए कि क्या उन्हें बार-बार चुनावी रणभूमि में उतरना पसंद है?

राष्ट्रीय चुनावों के साथ-साथ राज्यों के चुनाव होने से क्षेत्रीय दलों को राष्ट्रीय दलों के साथ प्रतिस्पर्धा करने में कठिनाई हो सकती है। कुछ लोगों का मानना है कि एक साथ चुनाव कराने से लोकतंत्र कमजोर हो सकता है क्योंकि इससे राष्ट्रीय स्तर पर एक ही राजनीतिक दल का दबदबा हो सकता है। यह सब तर्क कमजोर है।

दुनिया के कई देशों में अलग-अलग चुनाव व्यवस्थाएं हैं। कुछ देशों में एक साथ चुनाव होते हैं, जबकि कुछ देशों में अलग-अलग समय पर चुनाव होते हैं।

स्वीडन, बेलजियम और दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों में राष्ट्रीय और स्थानीय चुनाव एक साथ कराए जाते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में राष्ट्रीय और स्थानीय चुनाव अलग-अलग समय पर होते हैं। बहरहाल, एक देश-एक चुनाव से देश के आम जनमानस में राष्ट्र की अवधारणा सशक्त होगी। भारत में साल 1967 तक

ल्यंगर

कैदार शर्मा

लेखक ल्यंगकार हैं।

जब से उन्होंने जनसंख्या बढ़ाने की अपील की है तब से इस विचार ने नत्थू के दिलीपदिगम में खलबली मचा दी है। उसने अपनी पत्नी को यह जब खबर सुनाई और कहा ‘भाग्यवान तीन बच्चे तो होने ही चाहिए।’ पत्नी की भूकूटियों में बल पड़ गया,बोली आपका दिमाग तो सही हालत में है या नहीं ? इस महंगाई में दो बच्चे ही ढंग से पल जाएँ,पढ़-लिखकर काम-धंधे लग जाएँ यही बहुत है।’

नत्थू ने फिर समझाने का प्रयास किया,बोला- वे कह रहे हैं कि जिस समुदाय की प्रजनन दर कम हुई उसका निकट भविष्या में अंत हो सकता है।

जनसंख्या की गाड़ी,कैसे बढ़े अगाड़ी

चीन,दक्षिणी कोरिया और ईरान आदि देशों की आबादी निरंतर घट रही है। नए बच्चे कम पैदा होने से जापान बूढ़ों का देश बनता जा रहा है। खुद की न सही देश,समाज विश्व के बारे में भी कुछ तो सोचो।’

पत्नी बीच में ही नत्थू की बात काटकर बोली- ‘‘यह मीडिया और राजनेता मिलकर तुमको पागल करके छोड़ेंगे।कभी कहतेहैं-‘बच्चे दो ही अच्छे’‘हम दो हमारे दो’। अब कह रहे हैं बच्चे तीन पैदा करो।

किसी जमाने में किसी सरकार ने ही कहा था कि बढ़ती जनसंख्या ही गरीबी और पिछड़ेपन के लिए जिम्मेदार है। जनसंख्या कम करने का अभियान चलाया गया। परिवार नियोजन के लिए ऐसा शिकजा कसा गया था कि अनिवार्य नसबंदी की आँधी चल पड़ी थी। भिखारी और कुँवारे तक गेहूँ के साथ घुण की तरह चपेट में आ गए थे। उसके बाद जनसंख्या में तेजी गिरावट आई। ब्रेक लगाते-लगाते भी जनसंख्या की गाड़ी ने

विश्व में सबको पछाड़कर भारत को आगे कर डाला।’’

पत्नी ने कहना जारी रखा- ‘अब इक्कीसवीं सदी की महिलाएँ पहले जैसी नहीं रही। शिक्षा और आर्थिक आत्मनिर्भरता ने उनकी आँखें खोल दी है। पुरुषों से किसी भी क्षेत्र में कमतर नहीं है। अलबत्ता तो वे शिक्षा और कैरियर को लेकर इतनी सचेत हैं कि जल्दी शादी करना ही नहीं चाहती। कुछ की विवाह के लड्डूओं में अब खास दिलचस्पी ही नहीं रही।

पत्नी की ज्ञान और समझ से भरी बातें सुनकर नत्थू ने भी अपना सूर बदलने में ही भलाई समझी। तत्काल उसने पत्नी के सूर में सूर मिलाकर कहा- ‘‘तुम्हारी बात सही है भाग्यवान, मनुष्य को अपने छोटे छोटे समुदायों के संकीर्ण स्वार्थों के घेरों से निकलकर एक बड़े समुदाय मानव समाज में अपने आप को विलीन कर देना चाहिए। भारतीय संस्कृति की’’माता पृथ्वी ,पुत्रो अहम्’’ यानि हम सबकी माता पृथ्वी है और हम सब इसकी संतान है।

इस धारणा को विश्व के सभी समुदायों को आत्मसात करने की आवश्यकता है। यदि कोई स्वाधंगत सोच के चलते अन्य उद्देश्य से जनसंख्या बढ़ाता है तो सोच आखिर में अविवेकपूर्ण ही सिद्ध होने वाली है।

एक व्यक्ति की रीति-नीति का परिणाम थोड़ा या बहुत किसी एक समुदाय पर ही नहीं बल्कि सम्पूर्ण मानव समाज,और सार्वजनिक व्यवस्थाओं पर भी पड़ता है। किसी एक भी बच्चे को इस धरती पर बिना सोचे समझे नहीं लाया जाना चाहिए। सबसे पहले माता-पिता को सोचने की जरूरत पड़ेगी कि क्या वे उसके लिए पर्याप्त पौष्टिक भोजन,वस्त्र,निवास,शिक्षा और चिकित्सा आदि की सुविधाएँ देकर एक सभ्य सुसंस्कृत और आत्मनिर्भर नागरिक बनाने की जिम्मेदारी वहन करने में सक्षम हैं ? हर व्यक्ति के साथ ही सड़क,बिजली,परिवहन सहित अनेक सार्वजनिक व्यवस्थाओं पर भी प्रभाव पड़ता है।

छुट्टियां, पर्यटन और हमारी सेहत

अभिव्यक्ति

अदिति सिंह भदौरिया

लेखक स्तंभकार हैं।

दि संबर् का अंत आ रहा है। यह इस साल की समाप्ति और नए वर्ष के आरंभ का समय भी है। यही बड़े दिन की छुट्टियों का भी वक़्त है। बात जब छुट्टियों की होती है तो हर घर में लगभग चर्चा का विषय होगा कि सर्दियों की छुट्टियों में कहा घूमने जाया जाए। कुछ लोग गर्मी की तलाश में रहेंगे तो कुछ सर्दी में बर्फ का आनन्द लेना चाहेंगे। लेकिन फिर भी कुछ जरूरी बातों का ध्यान हम नहीं ख़ूब पा रहे हैं। जैसे घूमने और जीवन को सुखमय क्षणों में व्यतीत करने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है?

हममें से सबका जवाब अलग-अलग होगा। कुछ परिवार के साथ घूमने को प्राथमिकता देंगे, कुछ दोस्तों के साथ को और कुछ एकल ही घूमने में स्वयं को आरामदायक महसूस करेंगे। सब अपने अनुभव तो बताएंगे, पर किसी का भी ध्यान दो महत्वपूर्ण बातों पर शायद ही जाए। पहला सेहत जिसके बिना जीवन का हर सुख अधूरा है। हम कितना भी पैसा कमा लें, कितना भी परिवार को महत्व दें। हमारे बहुत सारे दोस्त हो। तब भी अगर हम स्वस्थ नहीं हैं, तो सब सुख हमारे लिए गौण है। हमारा साथ अगर हमारा शरीर नहीं दे पा रहा है तो समझिए कि हमारे साथ कोई भी नहीं है। हम किसी की दया के पात्र तो हो सकते हैं, लेकिन सुख -दुख के साथी कभी नहीं हो सकते। हम अपने को एक बोझ मानने लगते हैं।

हर पल एक उम्मीद से सबको देखते हैं कि कोई चाहे हमसे हमारी सारी दौलत ले लें, पर

हमें स्वस्थ कर दें। यहां कुछ भांतियां भी है कि अगर आप बोड़ी बनाते हैं,आपके मसल्स है, या आप डाइटिंग करके दुबले है, तो आप स्वस्थ हैं।यह केवल एक भाँति है

स्वस्थ होने का दुबले होने से कोई तालमेल ही नहीं है। आज के जलवायु और खान-पान को देखते हुए कोई भी बीमारी किसी को भी हो सकती है। इसलिए आन्तरिक रूप से स्वस्थ होने की बहुत जरूरत है। हमारे आसपास का पर्यावरण भी हमारे स्वास्थ्य पर अपना प्रभाव डालता है। ग्लोबल वार्मिंग के चलते हर मौसम ने अपना अंदाज बदल लिया है। जिसका



कुप्रभाव हम पर पड़ रहा है, जिसे हम अभी भी समझने के लिए तैयार नहीं हैं। ना तो गर्मी में पहले जैसी तपिश है, जिसे सावन की बूँदें ठंडक दें सकें और ना ही सर्दियों में अपनी बर्फिली पहाड़ियों में कशिश बची है। ग़लती मानव की है, पर खामियाजा धरती के हर प्राणी को भुगतान पड़ेगा। बर्फ के पहाड़ भी मानव मन के भीतर जमी स्वार्थी परतों पर आश्चर्यचकित हैं। हमें यह समझना होगा कि पहाड़ों को भी सर्द भावनाओं की जरूरत है और गर्मी को भी अपनी भावनाओं को छलकाने का अधिकार है। समय आ गया है, जब हम प्रकृति का सम्मान करते हुए। प्राकृतिक संसाधनों की देखभाल करें और अपने जीवन को स्वस्थ रखते हुए प्रकृति के आशीर्वाद प्राप्त कर सकें।

दृष्टिकोण

राजेंद्र बज

लेखक स्तंभकार हैं।

दुनिया भर के तमाम विवादों का मूल कारण किसी एक पक्ष का एकतरफा सोच ही हुआ करता है। जिसके चलते समाधान के अभाव में न्यायपालिका का दरवाजा खटखटाया जाता है। लगातार तमाम तरह के बढ़ते विवादों के चलते न्याय की अपेक्षा करने वालों की कतार इतनी लंबी हो गई है कि अंतिम न्याय पाने की कोशिश में जिनगी का एक बड़ा भाग जाया हो जाता है। कभी-कभी तो व्यवस्थित रूप से जोड़ घटाव करने के उपरांत हासिल कुछ नहीं बचता। या कभी बचता भी है, तो लगभग न के बराबर। बात सिर्फ आर्थिक ही नहीं है, अपितु लंबी प्रतीक्षा और मानसिक संताप का भी यदि आर्थिक दृष्टि से मूल्यांकन करें, तो चौकाने वाले परिणाम हमारे सामने होंगे।

हालांकि जमाने में सब कुछ निर्विवाद नहीं हो सकता। कभी-कभी ऐसा भी होता है कि उभय पक्ष अपनी-अपनी जगह लगभग सही हो। ऐसी स्थिति में जब समाधान की कोई सूरत ही नजर नहीं आती हो, तब न्यायपालिका का सहारा लिया जाए, यहाँ तक तो सब ठीक है। लेकिन व्यवहार में देखा गया है कि कभी-कभी किसी मामले को लंबे समय तक टालने की दृष्टि से भी न्यायपालिका का सहारा लिया जाने लगा है। यही कारण है कि देश भर की तमाम अदालतों में मुकदमों की भरमार नजर आती है। ऐसी स्थिति में जिनके लिए वास्तव में न्याय अपेक्षित होता है, उन्हें भी लंबी कतार में लगने को बाध्य होना पड़ता है। ऐसी स्थिति में न्याय पाने की प्रक्रिया समय एवं धन साध्य हो जाती है।

इन संदर्भों में आपके हमारे लिए यह अत्यंत आवश्यक

हम ही सही हैं, यह सोच सही नहीं



हो जाता है कि हम सुलह का रास्ता अखिरकार करने की दिशा में गंभीरता का परिचय दें। वैसे भी न्यायपालिका की मध्यस्थता में अनेक तरह के विचाराधीन मामलों का लोक

अदालत द्वारा सुखद पटाक्षेप करने का प्रयास किया जाता रहा है। जिसमें उभय पक्ष के अभिभाषक वर्ग की अत्यंत सराहनीय भूमिका निकल कर आती रही है। समय की मांग के

अनुरूप यह सिलसिला अनवरत रूप से चलते रहना चाहिए। इससे कुल मिलाकर देश में उपलब्ध शारीरिक और मानसिक श्रम शक्ति का और भी समुचित दोहन होने का मार्ग प्रशस्त हो सकेगा। क्योंकि देश की ऊर्जा एवं चेतना का एक बड़ा भाग न्याय की अपेक्षा में खोया-खोया नजर आता है।

दरअसल त्वरित न्याय के लिए देश में ऐसा वातावरण बनाया जाना जरूरी है कि अक्वल तो विवाद हो ही नहीं, और हो तो भी सीमित मात्रा में। इसके लिए हर एक आदमी को एकतरफा सोच की स्थिति से उबरना होगा, इस दिशा में सामाजिक प्रभाव एवं दबाव भी कारगर हो सकता है। इसके अतिरिक्त न्यायपालिका एवं अभिभाषक वर्ग की भूमिका भी अत्यंत महत्वपूर्ण होगी। वैसे तो न्यायपालिका एवं अभिभाषक वर्ग का हर संभव प्रयास त्वरित न्याय की दिशा में ही होता है। लेकिन मुकदमों की

बहुतायत के चलते इसका प्रत्यक्ष परिणाम कहीं दिखाई नहीं देता। जिसका नतीजा होता है कि तारीख पर तारीख और तारीख पर तारीख ही मिलती चली जाती है।

इसके चलते विलंबित न्याय, अन्याय के प्रतिरूप में ही दिखाई देने लगता है। ऐसी स्थिति में तथाकथित त्वरित न्याय हेतु कुछ एक मामलों को तो बिना कानूनी प्रावधान का सहारा लिए गलत रास्ता भी अपना लिया जाता है। जिसके चलते कानून और व्यवस्था पर भी आंच जाने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। खैर, मुद्दे की बात यह कि उपरोक्त स्थितियों को मद्देनजर रखते हुए यदि एकतरफा विचारधारा के बजाय निष्पक्ष एवं तटस्थ दृष्टि से किसी मामले का आकलन किया जाए, तो सहज रूप से अदालत से परे मामले का समाधान संभव हो सकता है। इस दिशा में सामाजिक नेतृत्व अपने समाज में ऐसा वातावरण निर्मित कर सकता है कि विभिन्न समाजों के बीच एक संतुलन का वातावरण निर्मित हो सके।

जाहिर है कि जब इस प्रक्रिया का विस्तार होने लगेगा, सारा का सारा सामाजिक परिवेश ही शांति का पुजारी बन जाएगा। अन्यथा हालात ऐसे ही रहे तो दिनोंदिन बढ़ती मुकदमों की संख्या न्याय को और भी अधिक समय व धन साध्य बनाकर रख देगी। जिसके चलते सामाजिक सद्भाव पर तो विपरीत असर पड़ेगा ही अपितु कानून और व्यवस्था के समक्ष भी गंभीर चुनौती उपस्थित हो सकती है। वैसे भी अधिकतर धन संपत्ति एवं अपराध के मामले विचाराधीन रहा करते हैं। ऐसे में धन संपत्ति के मामले में आपराधिक वर्ग के हस्तक्षेप को पूरी तरह से नहीं रोका जा सकेगा। यह स्थिति आम नागरिकों के सामान्य जनजीवन पर भारी भी पड़ सकती है। इसलिए यह जरूरी है कि हर कोई अपने एकतरफा सोच विचार का परित्याग करके चले।

छत्तीसगढ़ में नया पर्यटन स्थल धुड़मारास

सरोकार

डॉ. चन्दर सोनाने

लेखक मग जनसंपर्क विभाग के सेवानिवृत्त अधिकारी हैं।

देश का छत्तीसगढ़ राज्य आदिवासी बहुल प्रदेश है। य्ं तो छत्तीसगढ़ नक्सलियों के आतंक के केन्द्र के रूप में देशभर में ज्यादा प्रसिद्ध है। किन्तु कुछ महीनों से छत्तीसगढ़ के वनों से आच्छादित क्षेत्र में आदिवासियों की ही ग्राम सभा धुड़मारास की सामुदायिक वन संसाधन समिति द्वारा बनाए गए

सुरक्षा के लिए पहरेदारी करते हैं। सबकी ड्यूटी लगती है। जो व्यक्ति पहरेदारी में नहीं पाया जाता है, उस पर अर्थदंड लगाया जाता है। जो उसको देना अनिवार्य होता है।

ग्राम सभा धुड़मारास के युवा अध्यक्ष श्री सोनादार बघेल अपनी ग्राम सभा के गठन की जानकारी देते हुए उत्साह से बताते हैं कि हमारे गाँव में

खुद को इतना सक्षम बनाना पड़ेगा कि खुद इतना कमा सके कि अपना परिवार अच्छी तरह से चला सके। इसके लिए उसने अपने जैसे मित्रों का सहयोग लेकर अपने ग्राम में ग्राम सभा का गठन किया। फिर इसके बाद सामुदायिक वन प्रबंधक समिति और इको विकास समिति का गठन किया। ग्राम सभा धुड़मारास के अध्यक्ष श्री बघेल ने इस गाँव को पर्यटन के आकर्षण का केन्द्र कैसे बनाया ? इसकी कहानी बताते हुए वे कहते हैं कि उन्होंने बाहर से बांस बुलाकर उससे नाँव बनाई। इस नाँव को ग्राम के बीच से बहने वाली नदी में चलाया। इसका उन्होंने बाम्बु राफ्टिंग नाम दिया। ग्राम सभा द्वारा नदी में बांस की नाँव चलाकर बाम्बु राफ्टिंग का आनंद लेने के लिए प्रति व्यक्ति से 200

सब पूछने पर वे उत्साह से बताते हैं, कि हम कुछ करना चाहते थे, किन्तु क्या करें? यह समझ में नहीं आ रहा था। तब हमारे यहाँ के वनमंडलाधिकारी महोदय ने हमें अपना पूरा सहयोग और मार्गदर्शन दिया। उन्हीं के मार्गदर्शन के कारण हम यह सब कर सके हैं।

युवा अध्यक्ष बघेल बताते हैं कि बाम्बु राफ्टिंग और कायाकिंग के अलावा उन्होंने गाँव में पर्यटकों को रहने और छत्तीसगढ़ का भोजन उपलब्ध कराने के लिए होम स्टे भी बनाएँ हैं। यहाँ पर्यटकों को छत्तीसगढ़ का भोजन और रहने की सुविधा रियायती दर पर उपलब्ध कराते हैं।

यदि आदिवासियों को सही मार्गदर्शन और सहयोग मिल जाए तो वे आत्मनिर्भरता का अनुभव उदाहरण



एक नए पर्यटन केन्द्र के रूप में यह ज्यादा ख्याति प्राप्त कर रहा है।

छत्तीसगढ़ के दोंवाड़ा से करीब 70 किलोमीटर दूर सघन वन में ग्रामसभा धुड़मारास है। इस ग्रामसभा ने अपनी सामुदायिक वन संसाधन प्रबंधन समिति गठित की है। इस समिति में ग्राम के सभी 45 घरों से 2-2 सदस्य लिए गए हैं। इन 2 सदस्यों में से एक पुरुष और एक महिला है। इन सभी की जिम्मेदारी यह है कि ये 24 घंटे अपने क्षेत्र के वन और जल की

केवल 45 घर हैं। ग्राम सभा के गठन के लिए प्रत्येक घर से एक पुरुष और एक महिला को लिया गया है। इस प्रकार कुल 90 सदस्य हैं। सभी आदिवासी हैं। ये सब अपने गाँव के जल और जंगल की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है।

केवल 5 वीं तक पड़े युवा अध्यक्ष श्री बघेल बताते हैं कि पहले घर चलाना बड़ा मुश्किल होता था। सब जैसे-तैसे अपना परिवार चला रहे थे। एक दिन ऐसे ही उन्हें ध्यान आया कि सरकार या किसी भरोसे रहने की जरूरत नहीं। हमें

रूपए शुल्क लेना तय किया गया। प्रत्येक नाँव में 4 लोगों के बैठने के लिए बाँस से ही आसने-सामने बैच बनाई गई। इसमें अनिवार्य रूप से पर्यटकों को लाइफ जैकेट भी पहनाई जाती है।

बाम्बु राफ्टिंग के अतिरिक्त एक नाँव में एक व्यक्ति को घुमाने ले जाने की भी व्यवस्था की गई है, जिसका नाम उन्होंने दिया है, कायाकिंग। ग्राम सभा ने प्रति व्यक्ति इसका शुल्क 100 रूपए तय किया है। श्री बघेल को यह सब जानकारी कहीं से और कैसे मिली ? यह

प्रस्तुत कर सकते हैं। इसका ज्वलंत उदाहरण हैं, ग्राम सभा धुड़मारास। कुछ महीनों पहले ही शुरू हुई इस पहल के कारण आज गाँव के 45 घरों के सभी परिवारजन सुख पूर्वक अपना जीवन निर्वाह कर रहे हैं। आज ग्राम सभा धुड़मारास द्वारा पर्यटकों के लिए दी गई सुविधा बाम्बु राफ्टिंग और कायाकिंग देशभर में प्रसिद्ध हो चुकी है। कोई भी इसे गूगल पर देख कर आ सकता है। ग्राम सभा धुड़मारास हर पर्यटक के स्वागत के लिए तैयार है।

खेल जगत

नूपेन्द्र अभिषेक नूप

लेखक स्तंभकार हैं।

भारतीय क्रिकेट हमेशा से स्पिन गेंदबाजों का गढ़ रहा है। इस परंपरा ने क्रिकेट की दुनिया को अनिल कुंबले, हरभजन सिंह, और रविचंद्रन अश्विन जैसे विश्वस्तरीय खिलाड़ी दिए हैं। हाल ही में रविचंद्रन अश्विन ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है, और उनके इस निर्णय ने क्रिकेट प्रशंसकों को भावुक कर दिया है। अश्विन ने न केवल भारतीय क्रिकेट को ऊंचाइयों पर पहुंचाया, बल्कि विश्व क्रिकेट में भी अपने कौशल का परचम लहाया।

रविचंद्रन अश्विन का जन्म 17 सितंबर 1986 को चेन्नई, तमिलनाडु में हुआ था। उन्होंने अपनी शिक्षा सेंट बेड्स स्कूल से प्राप्त की और बाद में एसएएसएन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से इंजीनियरिंग की डिग्री ली। हालांकि उनका झुकाव हमेशा क्रिकेट की ओर रहा। शुरू में एक बल्लेबाज के रूप में खेलने वाले अश्विन ने जल्दी ही महसूस किया कि उनकी असली प्रतिभा ऑफ स्पिन गेंदबाजी में है। अश्विन ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में जिम्बाब्वे के खिलाफ वनडे मैच से की। इसके बाद उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में भी अपनी जगह बनाई और अपने पहले ही टेस्ट मैच में 9 विकेट लेकर अपनी प्रतिभा का परिचय दिया।

रविचंद्रन अश्विन का क्रिकेट करियर आंकड़ों के लिहाज से अद्वितीय रहा है। उन्होंने 94 टेस्ट मैचों में 474 विकेट लिए, जो उन्हें भारतीय क्रिकेट के सबसे सफल गेंदबाजों में से एक बनाता है। इसके अलावा, वनडे और टी20 प्रारूप में भी उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया। अश्विन ने न केवल गेंदबाजी में बल्कि बल्लेबाजी में भी भारतीय टीम को मजबूती दी। उन्होंने 5 शतक और 13 अर्धशतक बनाए हैं, जो यह दर्शाता है कि वे एक ऑलराउंडर के रूप में कितने सक्षम थे। अश्विन ने वनडे में 151 विकेट और टी20 में 72 विकेट लिए। हालांकि, उनका प्रमुख योगदान टेस्ट क्रिकेट में ही देखा गया।

अश्विन का गेंदबाजी स्टाइल उन्हें सबसे अलग बनाता है। उनकी ऑफ स्पिन गेंदबाजी में विविधता, फ्लाइट, और गति का अद्भुत संयोजन देखने को मिलता है। उनकी 'कैरम बॉल' ने कई बल्लेबाजों को परेशान किया और उन्हें विश्व क्रिकेट में ख़ास पहचान दिलाई। उनकी गेंदबाजी में गहराई और बल्लेबाजों को पढ़ने की क्षमता उनकी सफलता का मूल कारण रही है।



अनिल कुंबले और हरभजन सिंह के संन्यास के बाद भारतीय टीम में एक ऐसे स्पिनर की जरूरत थी जो टेस्ट क्रिकेट में विकेट निकाल सके और कठिन परिस्थितियों में टीम का साथ दे सके। अश्विन ने इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाया। कुंबले की तरह, अश्विन ने भी टेस्ट क्रिकेट में निरंतरता और दृढ़ता दिखाई। हरभजन की तरह, उन्होंने भी आक्रामकता और बल्लेबाजों पर मानसिक दबाव बनाने की कला सीखी।

अश्विन की सफलता केवल भारतीय धरती तक सीमित नहीं रही। उन्होंने जैसी मजबूत टीमों के खिलाफ भी शानदार प्रदर्शन किया। खासकर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उनकी गेंदबाजी हमेशा यादगार रही है। 2016 में, अश्विन को आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर का खिताब मिला, जो उनकी प्रतिभा और योगदान को वैश्विक स्तर पर मान्यता देता है।

अश्विन का संन्यास भारतीय क्रिकेट के लिए एक युग के अंत जैसा है। हालांकि उन्होंने घरेलू क्रिकेट और आईपीएल में खेलना जारी रखने का संकेत दिया है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में उनकी अनुपस्थिति को महसूस किया जाएगा। उनके संन्यास का फैसला कई कारणों से लिया गया हो सकता है, जिनमें उम्र, शारीरिक थकान, और युवा खिलाड़ियों को मौका देने की

भावना शामिल हो सकती है। अश्विन का प्रभाव केवल उनके प्रदर्शन तक सीमित नहीं है। उन्होंने युवा खिलाड़ियों को प्रेरित किया है और स्पिन गेंदबाजी की नई परिभाषा गढ़ी है। उनकी सोच, तकनीक, और रणनीतियां भारतीय क्रिकेट के लिए एक धरोहर हैं। उन्होंने टीम इंडिया को कठिन परिस्थितियों से बाहर निकाला और कई मैच जिताए। उन्होंने दिखाया कि एक स्पिनर भी ऑलराउंडर बन सकता है। अश्विन के संन्यास के बाद भारतीय टीम को नई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। युजवेंद्र चहल, कुलदीप यादव, और अक्षर पटेल जैसे स्पिनर टीम में हैं, लेकिन अश्विन जैसी विविधता और अनुभव हासिल करने में समय लगेगा।

रविचंद्रन अश्विन का करियर भारतीय क्रिकेट के स्वर्णिम अध्यायों में दर्ज रहेगा। उन्होंने न केवल स्पिन गेंदबाजी को नई ऊंचाई दी, बल्कि भारतीय क्रिकेट के प्रशंसकों को कई यादगार पल भी दिए। उनके संन्यास के बाद टीम में उनकी कमी जरूर महसूस होगी, लेकिन उनके द्वारा स्थापित मानदंड आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बने रहेंगे। अश्विन को इस नई यात्रा के लिए शुभकामनाएं, और भारतीय क्रिकेट में उनके योगदान के लिए हमेशा आभार।

कैंसर वैक्सीन

डॉ. सत्यकांत त्रिवेदी

मनोचिकित्सक एवं मनोवैज्ञानिक विश्लेषक

रुस द्वारा कैंसर रोकने के लिए की गई वैक्सीन की घोषणा का मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से गहरा प्रभाव पड़ सकता है। इस तरह की घोषणाएं आमतौर पर आशा और सकारात्मकता की भावना को बढ़ाती हैं। कैंसर जैसी गंभीर और जीवन के लिए खतरा मानी जाने वाली बीमारी के संभावित इलाज की ऐसी खबर सुनकर मरीजों और उनके परिवारों में एक अलग सा सुकून महसूस होता है। वे भविष्य को लेकर अधिक आशावादी हो सकते हैं, जो उनकी मानसिक स्थिति में सुधार लाने का कार्य कर सकता है।

कई बार मरीजों और उनके साथ वालों में कैंसर को लेकर जो भय होता है, वह ऐसी बातों से कम हो जाता है। लोग इसे जीवन की अनिश्चितता से जुड़े भय के कम होने के रूप में देखते हैं। डैथ फोबिया का मनोवैज्ञानिक प्रभाव बेहद गहरा होता है, और इस तरह की घोषणा से लोगों के दिमाग में यह विश्वास पनपता है कि भविष्य में इस बीमारी का इलाज संभव हो जाएगा। यह दृष्टिकोण मनोवैज्ञानिक असुरक्षा की भावना को कम करने में मदद करता है।

यह स्वयं पर नियंत्रण (self-efficacy) की भावना को मजबूत करता है, क्योंकि लोग यह महसूस करते हैं कि उनके स्वास्थ्य पर उनका नियंत्रण है। कैंसर के मरीज अक्सर लंबी और थकाऊ उपचार प्रक्रिया से गुजरते हैं,



जो उनके मानसिक स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है। लेकिन कैंसर के टीके की खबर उन्हें यह विश्वास दिला सकती है कि उनका संघर्ष अनिश्चित काल तक जारी नहीं

रहेगा। इससे डिप्रेशन और चिंता के स्तर में कमी आ सकती है। इस घोषणा के कुछ संभावित नकारात्मक प्रभाव

सकता है। कैंसर से पीड़ित लोगों के प्रति समाज में सहानुभूति और समझ का स्तर बढ़ सकता है। जब लोग यह समझते हैं कि कैंसर अब एक 'असाध्य बीमारी'

नहीं रही, तो कैंसर से जुड़े कलंक और नकारात्मक सामाजिक धारणाएं धीरे-धीरे कम हो सकती हैं। इससे मरीजों का आत्म-सम्मान और सामाजिक समर्थन प्राप्त करने की क्षमता बढ़ सकती है। इस घोषणा का एक अन्य महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक पहलू हेल्थ केयर सिस्टम और विज्ञान पर लोगों के विश्वास से जुड़ा है। जब किसी सरकार या वैज्ञानिक संगठन द्वारा किसी घातक बीमारी के इलाज के लिए नई खोज की घोषणा की जाती है, तो आम पब्लिक का विश्वास हेल्थ केयर सिस्टम और वैज्ञानिकों में बढ़ता है। यह विश्वास महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे लोगों का झुकाव नई चिकित्सा तकनीकों और टीकाकरण के प्रति बढ़ता है। जो लोग पहले चिकित्सा विज्ञान और टीकाकरण के बारे में संशय में रहते थे, वे अब वैज्ञानिक शोध के महत्व को स्वीकार कर पाते हैं। कुल मिलाकर, रूस द्वारा कैंसर के टीके की घोषणा का मनोवैज्ञानिक प्रभाव कई स्तरों पर देखा जा सकता है। यह आशा, सकारात्मक दृष्टिकोण, स्वास्थ्य जागरूकता और सामाजिक समर्थन को बढ़ावा दे सकता है। हालांकि, मनोवैज्ञानिक दृष्टि से यह भी आवश्यक है कि लोगों को अवास्तविक अपेक्षाओं से बचाया जाए और उन्हें वास्तविकता के बारे में जागरूक किया जाए। इस घोषणा का सही संदेश जनता तक पहुंचाना और उम्मीदों को वास्तविक बनाए रखना कैंसर चिकित्सकों, मनोचिकित्सकों और मीडिया की जिम्मेदारी है।

मनीष बागवानी बने भाजपा संतनगर मंडल अध्यक्ष

● सिंधी समाज ने शॉल श्रीफल देकर किया अभिनंदन, वरिष्ठ जनों ने दी बधाई



भोपाल । भाजपा संत नगर मंडल के नए अध्यक्ष के रूप में मनीष बागवानी की नियुक्ति से सिंधी समाज में खुशी की लहर है। उनकी नियुक्ति पर समाज और भाजपा संत नगर द्वारा अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया, जिसमें कई प्रमुख समाजसेवियों और भाजपा नेताओं ने भाग लिया।समारोह के दौरान मनीष बागवानी का स्वागत शॉल और श्रीफल से किया गया। समाज के गणमान्य व्यक्तियों ने बागवानी की इस उपलब्धि पर उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दी। अभिनंदन करने वालों में प्रमुख रूप से राजेश बेलानी, मोहन लालवानी, पंचायत अध्यक्ष माधु चांदवानी, हरीश केसवानी, बसंत चेलानी, गुलाब जेटानी, कमल विधानी, कहैया इसरानी, पंडित जयकुमार शर्मा, राजू वर्मा, प्रदीप बरसेजा, सोनू रायचंदानी, वासुदेव झमतानी, शेड्डी चंदनानी, नवीन मनसुखानी आदि शामिल रहे।

5वीं और 8वीं बोर्ड परीक्षा का टाइम टेबल जारी

● 24 फरवरी से शुरू होगी

भोपाल (नप्र) । मध्य प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ने कक्षा 5 और 8 के लिए साल 2025 की परीक्षाओं की तारीखों का ऐलान कर दिया है। पांचवीं और आठवीं की परीक्षाएं 24 फरवरी 2025 से शुरू होंगी। आधिकारिक टाइम टेबल के अनुसार, पांचवीं कक्षा की परीक्षाएं 1 मार्च 2025 को खत्म हो जाएंगी। जबकि आठवीं कक्षा की परीक्षाएं 5 मार्च 2025 तक चलेंगी। दोनों ही कक्षाओं की परीक्षाएं पहली भाषा के पेपर (हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू और मराठी) से शुरू होंगी। पांचवीं की परीक्षा दूसरी भाषा के पेपर के साथ समाप्त होगी, जबकि आठवीं की परीक्षा तीसरी भाषा के पेपर के साथ आयोजित होगा।

पति से अफेयर के शक में महिला की हत्या

● जबलपुर में महिला ने किया चाकू से हमला पति को रंगे हाथ पकड़ने गई थी

जबलपुर । जबलपुर में पति से अफेयर के शक में पत्नी ने एक महिला की हत्या कर दी। शहर की प्रोफेसर कॉलोनी में महिला ने दो महिलाओं पर चाकू से हमला किया। गर्दन पर हुए वार के चलते एक की मौत हो गई, जबकि दूसरी की हालत गंभीर बताई जा रही है। उसे इलाके के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना माढ़ोताल थाना इलाके की है। जानकारी के मुताबिक शिखा नाम की महिला को शक था कि उसके पति का पड़ोस में ही रहने वाली महिला से अफेयर चल रहा है। इसी संदेह के चलते वो पति को रंगे हाथ पकड़ने के लिए उस महिला की सहेली के घर पहुंची थी। यहीं उसने चाकू से हमला किया। एक की रास्ते में मौत, एक की हालत गंभीर - वारदात को अंजाम देने के बाद शिखा मौके से फरार हो गई है। स्थानीय लोगों ने गंभीर रूप से घायल दोनों को इलाज के लिए निजी अस्पताल पहुंचाया। एक को हालत गंभीर होने के चलते उसे मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया, लेकिन रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया। वहीं, मृतका की सहेली की हालत नाजुक बनी हुई है। युवती की हत्या करने वाली महिला वारदात के बाद मौके से फरार हो गई। जानकारी लगते ही माढ़ोताल थाना पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी महिला की तलाश शुरू कर दी। थाना प्रभारी विपिन तासकार ने बताया-शिखा के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर, उसकी तलाश शुरू कर दी है। प्राथमिक जांच में पाया गया है कि शक के संदेह पर हत्या की गई है।

एम्स शोधार्थियों का एपीपीआईकॉन राष्ट्रीय सम्मेलन में शानदार प्रदर्शन

भोपाल। एम्स भोपाल के कार्यपालक निदेशक प्रो. (डॉ.) अजय सिंह के मार्गदर्शन में, संस्थान ने एक बार फिर चिकित्सा अनुसंधान और नवाचार के क्षेत्र में अपनी उत्कृष्टता को साबित किया है। एम्स भोपाल के पीएचडी छात्रों ने चेन्नई में आयोजित एपीपीआईकॉन 2024 (एसोसिएशन ऑफ फिजियोलॉजिस्ट्स एंड फार्माकोलॉजिस्ट्स ऑफ इंडिया सम्मेलन) में अपने शोध प्रस्तुत किए। सम्मेलन में प्रस्तुत शोधों में प्रमुख रक्ष डॉ. राहुल गौर का अध्ययन, जिसमें रिपिटिटिव ट्रांसक्रैनिअल मैग्नेटिक स्टिमुलेशन के जरिए क्रॉनिक लो बैक पेन के प्रबंधन के लिए एक नवीन, गैर-आक्रामक चिकित्सा दृष्टिकोण प्रस्तुत किया गया। डॉ. संतोष वाकोडे, डॉ. वरुण मल्होत्रा, और डॉ. सोफिया मुद्दा के मार्गदर्शन में किए गए इस केस स्टडी ने पीढ़ा में उल्लेखनीय कमी, हृदय गति परिवर्तनशीलता में सुधार, और रोगियों में बेहतर संज्ञानात्मक प्रदर्शन (पी 300 लेटेसी में कमी) प्रदर्शित किया। यह शोध एम्स भोपाल में स्थापित उन्नत आरटीएमएस लैब और संस्थान के अत्याधुनिक चिकित्सा अनुसंधान के प्रति प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है। एक अन्य प्रस्तुति तनुशा पाठक द्वारा दी गई, जिसमें पीसीओएस (पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम) फेनोटाइप्स में नौद, चिंता और जीवन की गुणवत्ता का मूल्यांकन किया गया। डॉ. सोफिया मुद्दा और डॉ. संतोष वाकोडे के मार्गदर्शन में किए गए इस अध्ययन ने विभिन्न पीसीओएस फेनोटाइप्स के बीच मनोवैज्ञानिक और जीवन गुणवत्ता में महत्वपूर्ण अंतर उजागर किए। गंभीर फेनोटाइप (ए और बी) में कमजोर परिणाम पाए गए, जबकि फेनोटाइप डी में सबसे बेहतर परिणाम देखे गए। यह शोध फेनोटाइप-विशिष्ट प्रबंधन की आवश्यकता और पीसीओएस उपचार में मानसिक स्वास्थ्य देखभाल के समावेश को रेखांकित करता है। इस सम्मलेन के महत्व पर प्रो. सिंह ने कहा, यह एम्स भोपाल के लिए गर्व का क्षण है।

गृह मंत्री शाह के खिलाफ कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन, पुलता जलाया

● संविधान से देश चलता है, अमित शाह देश की जनता से माफी मांगे, भाजपा का चरित्र हुआ उजागर

भोपाल। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी अनुसूचित जाति विभाग के अध्यक्ष प्रदीप अहिरवार के नेतृत्व में आज प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय के समीप कांग्रेसजनों ने बाबा साहेब अमर रहें के नारे लगाकर संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर का अपमान करने और उनकी आलोचना करने के विरोध में देश के गृह मंत्री अमित शाह का पुतला दहन कर विरोध प्रदर्शन किया।

श्री अहिरवार ने कहा कि संवैधानिक पद पर बैठे अमित शाह ने जिस तरह लोकसभा में सार्वजनिक तौर पर अंबेडकर जी का अपमान किया है, जिस संविधान की शपथ लेकर अमित शाह देश के गृह मंत्री बनकर बैठे हैं, उसी संविधान निर्माता का अपमान केंद्र की मोदी सरकार और उसमें बैठे मंत्री और भाजपा नेताओं द्वारा किया जाना उनका चाल, चरित्र और चेहरा उजागर

करती है। अमित शाह की सोच और मानसिकता दिवालिया हो चुकी है, उन्हें किसी अच्छे सर्जन से अपना मानसिक इलाज कराने की जरूरत है। जब देश का गृह मंत्री ही संविधान निर्माता बाबा साहेब का अपमान करे तो देश की कानून व्यवस्था कैसी चलेगी, यह देश की जनता समझ सकती है?

श्री अहिरवार ने कहा कि बाबा साहेब ने दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों और महिलाओं को संविधान में प्रदत्त अधिकार दिये, वे सर्वहारा वर्ग के मसीहा हैं। देश की जनता को समतामूलक, समावेशी भावना को दृष्टिगत रखते हुये



स्वतंत्रता से जीने के मौलिक अधिकार दिये, उसी की परिणिाति है कि आजादी के बाद आज तक हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं। देश संविधान से चलता है। अमित शाह ने लोकसभा में जिस प्रकार से बाबा साहेब अंबेडकर जी का अपमान किया है, देश की जनता से उनको माफी मांगना चाहिए। केंद्र की मोदी सरकार को अमित शाह को गृह मंत्री के पद से इस्तीफा लेना चाहिए।

श्री अहिरवार ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि अमित शाह ने देश की जनता से माफी नहीं मांगी तो कांग्रेस अनुसूचित जाति विभाग को पूरा अजा वर्ग अमित शाह के खिलाफ मोर्चा खोलेगा, उग्र आंदोलन कर मध्यप्रदेश से लेकर दिल्ली तक कूच करने के लिए विवश होगा।

विरोध प्रदर्शन के दौरान मप्र कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष मुकेश नायक, पूर्व राज्यसभा सदस्य राजमणि पटेल, भूपेन्द्र गुप्ता, रवि सक्सेना, स्वदेशी शर्मा, अमित शर्मा, आनंद जाट, अभिनव बरोलिया, मिथुन अहिरवार, किशन अहिरवार, पवन पटेल, हेमंत नरवरीया, मुकेश बंसल, विनोद सूर्यवंशी, नीरज चंडावे, कुनाल गजभिये, टीआर गेहलोद, विकी कंडेर, शुभम इंद्रासे, दर्शन कोरी, जे.पी. रोहर, रामकन्हैया, विनोद बघेल, शुभम अहिरवार, विनय मालवीय सहित बड़ी संख्या में कांग्रेसजन उपस्थित थे।

रविन्द्र भवन भोपाल में ‘डकिया डाक लाया’ 22 को

मुंबई के विक्रम जीत के निर्दर्शन में संगीतमय शाम

भोपाल । महेश मेलेडी मूवमेंट (एम-श्री) ग्रुप 22 दिसंबर (रविवार) को रविंद्र भवन के अंजनी सभागार में ‘डकिया डाक लाया’ संगीतमयी आयोजन करने जा रहा है। यह कार्यक्रम शाम 6 बजे से शुरू होगा। ग्रुप के अध्यक्ष दिनेश गर्ग और वॉइस ऑफ किशोर

निर्देशन में की जाएगी।

क्लासिकल संगीत के इस आयोजन में की-बोर्ड पर दिवाकर परख (मुंबई), मुकुल शर्मा (ग्वालियर), लक्षित अय्यर (भोपाल), वायलिन पर रईस शाह (मुंबई), सेक्सोफोन पर मनीषा यादव (इंदौर), तुम्बा पर आकाश रणदेव (मुंबई), ऑक्टोपेड पर आयुषी मकवाना (ग्वालियर), लीड गिटार पर विकास जैन (इंदौर), बेस गिटार पर दुष्यन्त सचदेवा (भोपाल) जैसे प्रसिद्ध कलाकार अपने हुनर का प्रदर्शन करेंगे।

इस कार्यक्रम में मेल सिंगर्स के रूप में अशोक सिंह, अरविंद दयाल शर्मा, डॉ. जितेंद्र झारिया, मनोज पटवा, हरीश जहाँगीर, अनिरुद्ध सक्सेना, यश अग्रवाल, जोनोद शर्मा, सुशील कैथल, लक्षित अय्यर सहित फीमेल सिंगर्स मनीषा यादव, अमोषी मालवीय, माहुरी शर्मा, प्रतिमा गोस्वामी, अनन्या कुलश्रेष्ठ, वंदना सोनी, अंशिका राजौरिया, सर्वेस राजा, मीता दास, पररहत खान, रिकी सोनकर, रिया रसालिका अपनी मधुर आवाज का जादू बिखेरेंगे।



अरविंद दयाल शर्मा ने बताया कि इस कार्यक्रम में प्रत्येक आमंत्रण पत्र के साथ एक व्यक्ति का निःशुल्क प्रवेश होगा। कार्यक्रम की एंकरिंग प्रसिद्ध सिंगर और वॉइस ऑफ रफ़ी, अशोक सिंह द्वारा की जाएगी। वहीं, साउंड निबंधन का कार्य मनोज खरे सभालगे और संगीत संयोजन की जिम्मेदारी मुंबई के प्रसिद्ध कलाकार विक्रम जीत सिंह ‘विकी’ के

मुख्यमंत्री जन कल्याण अभियान में लापरवाही, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता निलंबित

भोपाल जिप सीईओ गांवों में पहुंचे; महिलाओं से पूछा- लाभ मिल रहा या नहीं?



भोपाल । मुख्यमंत्री जन कल्याण पर्व में लापरवाही बरतने पर भोपाल जिला पंचायत सीईओ ऋतुराज सिंह ने एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को निलंबित कर दिया। बुधवार को वे गांवों में पहुंचे थे। उन्होंने महिलाओं से पूछा कि उन्हें योजनाओं का लाभ मिल रहा है या नहीं? पर्व के तहत 11 दिसंबर से 26 जनवरी तक ग्राम पंचायतों में शिविर

लगाए जा रहे हैं। बुधवार को भी शिविर लगाए गए। इनमें सीईओ ऋतुराज भी शामिल हुए। उन्होंने ग्राम पंचायत फंदाकलां, ईटरखेड़ी छाप और बरखेड़ा नाथू पहुंचकर हितग्राहियों से चर्चा की। योजनाओं के बारे में जानकारी भी दी गई। जनपद फंदा सीईओ शंकर पांसे, एपीओ संदीप कुमार श्रीवास्तव भी साथ थे।

अधिकारी-कर्मचारी शिविर में

लहसुन की तस्करी पर रोक नहीं लगा रही सरकार

● किसानों में भारी आक्रोश : जीतू पटवारी

भोपाल। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी जी ने इंदौर के चौधराम मंडी पहुंचकर किसानों के साथ चीन के लहसुन विरोध में किसानों की आवाज उठाते हुये अपने एक वक्तव्य में चीन से अफगानिस्तान के रास्ते आने वाले भारी मात्रा में लहसुन पर रोक न लगाने की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि पश्चिम मध्य प्रदेश में किसान सड़कों पर उत्तकर आंदोलन कर रहे हैं। श्री पटवारी ने कहा है 2014 में भारत सरकार ने चाइनीस लहसुन को अमानत और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक बताकर प्रतिबंधित किया है। ऐसी स्थिति में हजारों टन लहसुन का आना मध्य प्रदेश के लोगों के स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है, इस लहसुन के बारे में कहा गया है कि यह पेट में अल्सर और अनेक प्रकार की बीमारियों का कारण हो सकता है। इलाहबाद हाईकोर्ट ने इस लहसुन को बेचे जाने पर रोक लगाकर फटकार लगाई थी और सख्त टिप्पणी की थी। श्री पटवारी ने कहा कि मध्य प्रदेश में खासतौर से पश्चिम मध्य प्रदेश में किसान बहुत बड़े मात्रा में लहसुन की खेती करता है। चीन का लहसुन आने से लहसुन के दाम 50 प्रतिशत तक गिर गए, जिसके कारण मध्य प्रदेश के किसानों की लागत भी नहीं निकल पा रही है। जिसके विरोध में हजारों किसान सड़क पर उत्तरकर आंदोलन कर रहे हैं। सब्जी मंडी पहुंचे श्री पटवारी जी ने किसानों को संबोधित करते हुये कहा कि किसानों द्वारा किये जा रहे इतने बड़े पैमाने पर आंदोलन को सरकार अनदेखा कर रही है और कोई प्रतिक्रिया भी नहीं दे रही। एक तरफ तो सरकार किसानों को समर्थन मूल्य नहीं दे रही है, दूसरी तरफ चीन से होने वाली लहसुन की तस्करी पर रोक भी नहीं लग पा रही है, जिससे किसानों में भारी निराशा है। श्री जीतू पटवारी ने कहा कि किसानों की एक-एक लड़ाई को कांग्रेस सड़क से लेकर सदन तक लड़ेगी और इस किसान विरोधी प्रदेश को भाजपा सरकार को किसी भी कीमत पर बेलगाम नहीं होने देगी। चाइना लहसुन का विरोध कर रहे किसानों की आवाज तराना के जुझारू विधायक महेश परमार जी के जरिए विधानसभा तक पहुंचाई गई।

एम्स भोपाल द्वारा चिकलोद कला गांव में

योग स्वास्थ्य और मेटेरियोविजिलेंस पर जागरूकता अभियान का आयोजन

भोपाल। एम्स भोपाल के कार्यपालक निदेशक प्रो. (डॉ.) अजय सिंह के नेतृत्व में आयुष विभाग, फार्माकोलॉजी विभाग और सामुदायिक एवं परिवारिक चिकित्सा विभाग के सहयोग से चिकलोद कला गांव के



प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और आंगनवाड़ी केंद्र में योग, स्वास्थ्य और मेटेरियोविजिलेंस पर जागरूकता अभियान आयोजित किया गया। इस आयोजन में दो मुख्य स्वास्थ्य कार्यक्रम शामिल थे: आयुष विभाग द्वारा आयोजित योग और स्वास्थ्य शिविर, और फार्माकोलॉजी विभाग द्वारा मेटेरियोविजिलेंस पर जागरूकता अभियान, जिसका उद्देश्य चिकित्सा उपकरणों और उपचारों की सुरक्षा और प्रभावकारिता के

बारे में ग्रामीणों को जानकारी देना था।

प्रो. सिंह ने इस पहल के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा, इस प्रकार के कार्यक्रम हमारे ग्रामीण समुदायों में स्वास्थ्य और भलाई को बढ़ावा देने के हमारे प्रयासों का हिस्सा है। योग और मेटेरियोविजिलेंस के बारे में ग्रामीणों को जागरूक करना महत्वपूर्ण कदम है, जो न केवल उन्हें अपने स्वास्थ्य और सुरक्षा के प्रति सचेत करता है, बल्कि उन्हें बेहतर जीवनशैली अपनाने के लिए भी प्रेरित करता है।

कार्यक्रम में आयुष विभाग द्वारा एक स्वास्थ्य शिविर आयोजित किया गया, जिसमें बच्चों और ग्रामीणों को योग सिखाया गया। इस शिविर का उद्देश्य ग्रामीणों को स्वस्थ जीवनशैली अपनाने के लाभ के बारे में जागरूक करना था। शिविर में स्वच्छता, संतुलित आहार, और नियमित व्यायाम के महत्व पर भी चर्चा की गई। इस सत्र में ग्रामीणों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और योगसन तथा प्राणायाम सीखा। इसके साथ ही, फार्माकोलॉजी विभाग द्वारा आयोजित मेटेरियोविजिलेंस जागरूकता अभियान का उद्देश्य समुदाय को चिकित्सा उपकरणों की सुरक्षा और प्रभावशीलता की निगरानी के महत्व के बारे में जानकारी देना था।

आईटी पार्क का सीएम करेंगे भूमिपूजन

अधिकारी साइट विजिट करने पहुंचे; हर फ्लोर पर होगी हाइटेक सुविधाएं

उज्जैन । उज्जैन में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 21 दिसंबर को आईटी पार्क का भूमि पूजन करेंगे। प्रथम चरण में 46 करोड़ रुपए की लागत से आईटी पार्क निर्मित होगा। आईटी पार्क

के बनने से कई बड़ी कंपनियों के ऑफिस उज्जैन में खुल सकेंगे। जिससे उज्जैन में आईटी से जुड़े छात्रों शहर से बाहर नहीं जाना होगा।उज्जैन कलेक्टर नीरज सिंह, एमपीआईडीसी के प्रबंध निदेशक राजेश राठौर, जिला पंचायत सीओ जयती सिंह, एडीएम अनुकूल जैन, निगम कमिश्नर आशीष पाठक ने इंजीनियरिंग कॉलेज के पास बनने वाले आईटी पार्क की जमीन को देखने के लिए पहुंचे। सीएम मोहन यादव यहीं पर शनिवार को आईटी पार्क का भूमि पूजन करेंगे। इसके लिए साइट को क्लियर करवाने का काम शुरू हो चुका है। एमपीआईडीसी के प्रबंध निदेशक राजेश राठौर ने बताया-कलेक्टर नीरज कुमार सिंह ने प्रशासनिक संकुल भवन के द्वितीय तल पर स्थित सभा कक्ष में आईटी पार्क के भूमि पूजन की तैयारियों के संबंध में संबंधित शैक्षणिक संस्थानों के पदाधिकारियों के साथ बैठक लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए।दो

फेज में आईटी पार्क का निर्माण होगा -राजेश राठौर ने बताया कि उज्जैन शहर के लिए आईटी पार्क की सौगात बहुत ही महत्वपूर्ण है। आईटी पार्क बनने से छात्रों को बेहतरीन उच्च गुणवत्ता



की शिक्षा प्राप्त होगी और उज्जैन शहर के लिए औद्योगिक विकास को भी निरंतर वृद्धि होगी। उज्जैन में शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज के समीप आईटी पार्क का निर्माण किया जाएगा। आईटी पार्क शुरू होने से स्थानीय अर्थव्यवस्था में बूम आएगा।आर्वाटिक्ट भूमि में दो फेज में पार्क का निर्माण होगा। प्रथम चरण में लगभग 5400 वर्गमीटर क्षेत्र में निर्माण किया जाएगा।

जिससे लगभग 1.2 लाख वर्ग फुट आवांटन योग्य आईटी स्पेस का निर्माण किया जाएगा। लगभग 30 आईटी इंडस्ट्री अपना प्लग एंड प्ले आधारित मॉडल पर कार्य प्रारंभ कर सकेंगी।

उज्जैन में निवेश के नए अवसर पैदा होंगे जिससे स्थानीय रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। इसके लिए दो साल की डेडलाइन आते की गई है। **ऐसा होगा उज्जैन का आईटी पार्क** -एमपीआईडीसी के राजेश राठौर ने बताया कि हम इस आईटी पार्क में टेक कंपनियों और स्टार्टअप को सभी तरह की एडवांस सुविधाएं देंगे। यह उज्जैन का अपने आप में पहला पार्क होगा। सरकार का इस बात पर जोर है कि स्थानीय युवाओं को इसमें प्राथमिकता दी जाए। आईटी पार्क से उज्जैन में औद्योगिक विकास को भी बढ़ावा मिलेगा। आईटी पार्क 2.161 हेक्टर जमीन पर बनेगा। इसमें 11239 स्केयर मीटर में बिल्डिंग बनेंगी, बिल्डिंग की ऊंचाई 31.7 मीटर होगी। जिसमें हर फ्लोर पर टॉयलेट के साथ कैफेटेरिया ड्रिंकिंग वाटर, लिफ्ट के साथ ऑफिस के लिए हाईटेक सुविधा भी मिल सकेंगी। इस बिल्डिंग में ग्राउंड फ्लोर पर 59 कार पार्क हो सकेंगी।

श्रद्धा सेतु एक्सप्रेस सहित तीन ट्रेन सुल्तानपुर तक जाएंगी, 24 दिसंबर से बदलेगा रूट

जबलपुर। जबलपुर होकर अयोध्या केंट तक संचालित होने वाली तीन साप्ताहिक एक्सप्रेस ट्रेन 24 दिसंबर से 7 जनवरी के मध्य सुल्तानपुर तक जाएंगी। ये तीनों ट्रेन, एलटीटी-अयोध्या केंट (22183/84),



एलटीटी-अयोध्या केंट-एलटीटी (22103/04) और रामेश्वरम-अयोध्या केंट-रामेश्वरम श्रद्धा सेतु (22613/14) एक्सप्रेस है।संबंधित अवधी में एलटीटी-अयोध्या-एलटीटी (22103/04) और श्रद्धा सेतु (22613/14) एक्सप्रेस अपने निर्धारित मार्ग के स्थान पर जफराबाद-जौनपुर सिटी (परिवर्तित मार्ग) होकर चलेंगी। उक्त ट्रेनों संचालन भी अयोध्या

केंट के स्थान पर सुल्तानपुर स्टेशन से आरंभ होगा। यह निर्णय अयोध्या केंट स्टेशन में यार्ड रिमाडिंग कार्य के कारण किया गया है। इस दौरान उक्त रेलवे लखनऊ मंडल के बाराबंकी-अयोध्या केंट-जफराबाद रेलखंड पर अधोसंरचना निर्माण कार्य होना है। इसके कारण भी कुछ अन्य ट्रेनों का परिचालन भी प्रभावित रहेगा। दुर्ग- नौतनवां 18205 एक्सप्रेस 19, 26 दिसंबर व दो जनवरी और नौतनवां-दुर्ग 18206 एक्सप्रेस 21, 28, दिसंबर एवं चार जनवरी को दोनों दिशाओं में अपने पूर्व मार्ग के स्थान पर मानिकपुर-प्रयागराज छिवकी-वाराणसी-जौनपुर-औरिहार होकर जाएगी।

गोरखपुर-यशवंतपुर 15023 एक्सप्रेस 24, 31 दिसंबर एवं सात जनवरी और यशवंतपुर-गोरखपुर 15024 एक्सप्रेस 19, 26, दिसंबर एवं दो जनवरी को अपने पूर्व मार्ग के बजाय गोरखपुर-गोंड-बाराबंकी होकर संचालित होगी। इस दौरान छपरा-एलएलटी-छपरा एक्सप्रेस (15101/02) छपरा-गोरखपुर-गोंड-बाराबंकी-ऐशबाग-कानपुर सेंट्रल होकर चलेंगी।

